RNI No. : TNHIN/2013/52520 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 290 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » मंगलवार » 19-05-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 पिछली सरकारों की सोच 'कट्टा' और बम तक ही सीमित थी : आदित्यनाथ
6 चीन-अमेरिका की निकटता से भारत के सामने वैश्विक चुनौतियां
7 बॉक्स ऑफिस पर 'करुप्पु' का दबदबा

फर्स्ट टेक

प्रधानमंत्री मोदी को मिला नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

ओस्लो/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोमवार को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया। मोदी को यह सम्मान भारत-नॉर्वे संबंधों को आगे बढ़ाने में उनके योगदान और उनके नेतृत्व के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' प्रदान किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, ''ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। यह सम्मान भारत की जनता को समर्पित है और भारत तथा नॉर्वे के बीच अटूट मित्रता का प्रतीक है। यह वैश्विक प्रगति के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।''

ईडी ने आप नेता दीपक सिंगला को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली और गोवा में छापेमारी के बाद कथित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सिंगला दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र से आप के उम्मीदवार थे। ईडी ने 2024 में भी जांच के सिलसिले में उनके घर पर छापा मारा था। धन शोधन का यह मामला बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होने के बाद सिंगला को गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर इकबाल मिर्ची, उसके परिजनों से जुड़ी 700 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से जुड़े एक मामले में मुंबई के वर्ली स्थित तीन प्रमुख इमारतों समेत 700.27 करोड़ रुपए मूल्य की उनकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के वर्ली स्थित राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू शामिल हैं, जिनका मूल्य लगभग 497 करोड़ रुपए आंका गया है। इसके अलावा दुबई में स्थित लगभग 203.27 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी संपत्तियों को भी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है।

कसी भी मुद्दे का समाधान केवल सैन्य संघर्ष से नहीं किया जा सकता

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया व यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ओस्लो/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नॉर्वे के उनके समकक्ष जोनास गहर स्टोर के बीच व्यापक वार्ता हुई जिस दौरान उन्होंने यूक्रेन व पश्चिम एशिया में तनाव को संवाद और कूटनीति के माध्यम से हल करने का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने सोमवार को स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता, नीली अर्थव्यवस्था, हरित परिवहन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और आर्कटिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की।

मोदी ने मीडिया के लिये टेलीविजन पर प्रसारित अपने संदेश में कहा, भारत और नॉर्वे, दोनों ही नियम-आधारित व्यवस्था, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि किसी भी मुद्दे का समाधान केवल सैन्य संघर्ष से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के लिए किए जा रहे हर प्रयास का समर्थन करना जारी रखेंगे।

भारत-नॉर्वे संबंधों पर विस्तार से चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि इन संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से, हमारी कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु अनुकूलन तक, और नीली अर्थव्यवस्था से लेकर हरित नौवहन तक - विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक समाधान विकसित करेंगी, जिसमें भारत के पैमाने, गति और प्रतिभा को नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के साथ जोड़ा जाएगा।

वी.डी. सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ

केरल में वाम मोर्चे को सत्ता से बेदखल कर 10 साल के बाद फिर से कांग्रेस नीत यूडीएफ की सरकार बनाने में निभायी अहम भूमिका

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सतीशन के 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल को भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई।

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल में वाम मोर्चे को सत्ता से बेदखल कर 10 साल के बाद फिर से कांग्रेस नीत यूडीएफ की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले वी.डी. सतीशन ने सोमवार को यहां सेंट्रल स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

सतीशन के 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल को भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में वरिष्ठ और युवा नेताओं को जगह दी गई है। एक समय मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार माने जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेता राहुल गांधी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता समारोह में मौजूद रहे। यूडीएफ में शामिल अहम सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) को भी मंत्रिमंडल में पर्याप्त जगह मिली और नई सरकार में गठबंधन संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखी।

करीब डेढ़ घंटे तक चले शपथ ग्रहण समारोह और लोक भवन में आयोजित चाय समारोह के बाद राज्य सचिवालय में सतीशन की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में मार्च में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के दौरान राहुल गांधी द्वारा घोषित पांच कार्यक्रमों में से दो को लागू करने का फैसला लिया गया।

इनमें 15 जून से केएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और बुजुर्गों के लिए एक समर्पित विभाग स्थापित किया जाना शामिल है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह विभाग देश में अपनी तरह का पहला विभाग होगा।

चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा घोषित अन्य गारंटियों में कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपए का वजीफा, सामाजिक कल्याण पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए करना, प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और युवा उद्यमियों को पांच लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देना शामिल है।

नीट पेपर लीक मामले में:

कोचिंग सेंटर संस्थापक मोटेगांवकर नौ दिन की सीबीआई हिरासत में

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में रेनुकाई करियर सेंटर के संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को सोमवार को नौ दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। अदालत ने कहा कि जांच फिलहाल प्रारंभिक चरण में है।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए 10 दिनों की हिरासत मांगे जाने के बाद, आरोपी से नौ दिनों की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दे दी।

न्यायाधीश ने केंद्रीय एजेंसी की उन दलीलों पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि मोटेगांवकर ने उन सभी लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया है, जिन्हें नीट-यूजी 2026 (उसने देशभर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अनिवार्य प्रवेश परीक्षा) के लीक हुए प्रश्नपत्रों की हाथ से लिखी प्रतियां मुहैया कराई थीं।

न्यायाधीश ने कहा, आरोपी शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की हिरासत इस अपराध में शामिल अन्य सह-आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मांगी गई है। इसके साथ ही नीट 2026 परीक्षा और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े डिजिटल उपकरणों/डिजिटल सबूतों और बातचीत के रिकॉर्ड को बरामद करने व उनका विश्लेषण करने तथा वित्तीय लेन-देन का पता लगाने के लिए भी यह हिरासत आवश्यक है।

न्यायाधीश गुप्ता ने कहा कि आरोपी की हिरासत इसलिए भी मांगी गई है ताकि वह सबूतों के साथ आगे कोई छेड़छाड़ न कर सके और इस मामले से जुड़ी बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके।

तमिलनाडु में टीवीके सरकार जल्द बेनकाब हो जाएगी : उदयनिधि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तंजावुर (तमिलनाडु)/भाषा। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को दावा किया कि तमिलनाडु की तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) नीत सरकार जल्द ही ''बेनकाब'' हो जाएगी।

यहां एक विवाह समारोह में उदयनिधि स्टालिन ने कहा, ''सरकार बने महज 10 दिन हुए हैं और महिलाएं, युवा तथा वर्तमान पीढ़ी (जेन-जेड) इस प्रशासन का असली चेहरा पहचानने लगी है। जैसे-जैसे वक्त बीतेगा, सत्ता में बैठे लोग खुद को और भी उजागर करते जाएंगे।'' उन्होंने कहा, ''वक्त के साथ और भी सच्चाइयां लोगों के सामने आएंगी।''

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा, ''इसलिए हम एक बार फिर जनसेवा और जमीनी काम में जुट जाएं। जैसा हमारे नेता एम.के. स्टालिन हमेशा कहते हैं-सत्ता में रहते हुए ही नहीं, विपक्ष में रहकर भी काम करें। केवल अपने मतदाताओं के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी काम करें जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया।''

द्रमुक की सत्ता में वापसी का भरोसा जताते हुए उदयनिधि ने कहा कि पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। उन्होंने कहा, ''चुनाव में जीत और हार तो लगी रहती है। एक सामाजिक आंदोलन के रूप में द्रमुक हमेशा की तरह जनसेवा में लगी रहेगी और हम भी इस प्रतिबद्धता पर अडिग रहेंगे।''

टीवीके ने कोई जमीनी काम नहीं किया, सोशल मीडिया के जरिये जीत हासिल की : स्टालिन

तंजावुर (तमिलनाडु)/भाषा। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने सोमवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके ने कोई जमीनी काम नहीं किया, बल्कि लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावित कर तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को हुए चुनाव में जीत हासिल की।

स्टालिन ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी की कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें सम्मेलन और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े कार्य शामिल हैं। उन्होंने टीवीके का प्रत्यक्ष नाम लिये बिना आरोप लगाया कि उसने इस तरह से कोई जमीनी काम नहीं किया, जैसा कि द्रमुक ने किया। उनके अनुसार, कई जगहों पर तो टीवीके ने मतगणना एजेंट भी नियुक्त नहीं किए।

सरकार ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नागरिकता नियम,2009 के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वाले पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आवेदकों को अब अपने मूल देश से जारी स्वयं के पासपोर्ट की स्थिति के बारे में घोषणापत्र देना होगा। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी मिली।

मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हुए एक नया अनुच्छेद जोड़ा है, जिसके तहत आवेदक के पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों द्वारा जारी किया गया कोई वैध और/या समाप्त हो चुका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए।

राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि यदि आवेदक के पास सक्रिय पासपोर्ट है, तो उसे पासपोर्ट संख्या और जारी करने की तिथि और स्थान तथा समाप्ति तिथि जैसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उन्हें नागरिकता आवेदन की स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर अपना वैध और/या समाप्त हो चुका पासपोर्ट संबंधित वरिष्ठ डाक अधीक्षक या डाक अधीक्षक को सौंप दिए जाने का घोषणापत्र देना होगा।

यह नया प्रावधान नियमों की अनुसूची आईसी के बाद जोड़ा जाएगा, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए है जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए थे।

सूर्यास्त 19-05-2026	सूर्योदय 20-05-2026
6:28 बजे	5:42 बजे

BSE	NSE
75,315.04	23,649.95
(+77.05)	(+6.45)

सोना	चांदी
16,058 रु.	283,000 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

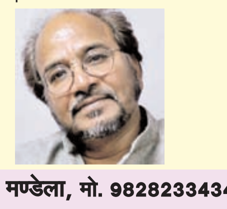

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

लाओ बदलाव

हो चुकी जीत अब तो छोड़ो,
परिवारवाद का आप राग।
भूलो अब उनके पुरखों को,
अपने वादों को करो याद।
अच्छा अब नहीं लगे सबको,
केवल निंदा या फिर विवाद।
छोड़ो चुनाव का स्थाई मूड,
वर्ना जन में होगा विषाद।।

महंगाई के मुद्दे पर खरगे का आरोप :

प्रधानमंत्री में दूरदर्शिता की कमी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/बेंगलूरु/भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में दूरदर्शिता का अभाव है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हालिया विधानसभा चुनावों से पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती तो भाजपा को इसका नुकसान होता।

खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''अगर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले पेट्रोल-डीजल समेत बाक़ी चीजों की कीमतें बढ़ा देते तो उन्हें बड़ा नुकसान होता। मोदी सरकार ने चुनाव तक सभी बातों को देश से छिपाकर रखा, लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो गए तो सभी चीजों की क़ीमतें बढ़ गईं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी में दूरदर्शिता में कमी है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''हम इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि भाजपा सरकार की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है। देश के गरीबों को वह जरूरी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं, जिनके वे हकदार हैं।''

शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की हत्या के मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर/बलिया (उप्र)/भाषा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक वांछित आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजकुमार सिंह को मुजफ्फरनगर जिले में दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरिद्वार से लौटते समय गिरफ्तार किया गया।

हमारे पड़ोसी ने जब भी 'नापाक हरकत' की, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया : राजनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत के पड़ोसी देश ने जब भी कोई नापाक हरकत की है, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी दुस्साहस का प्रभावी जवाब दिया जाएगा।

राजनाथ ने यह टिप्पणी वियतनाम की राजधानी हनोई में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए की। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा, जब भी हमारे पड़ोसी देश ने कोई 'नापक हरकत' की है - और 'नापक' से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मैं किसकी करतूतों की बात कर रहा हूं - तो उसे हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अब उसे दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए।

राजनाथ ने कहा, कभी-कभी आतंकवाद की मदद से अप्रत्यक्ष रूप से वे भारत को अस्थिर और कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सरकार की ओर से और देश के रक्षा मंत्री के रूप में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने का कोई भी प्रयास किया गया, तो हमारा देश प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम है और भारत प्रभावी ढंग से जवाब देगा।

रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी जिक्र किया।

जिस मंच से उन्होंने भाषण दिया, उसके पास 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित एक पोस्टर भी लगाया गया था।

राजनाथ ने कहा, हमारे रक्षा बलों ने (उस अभियान के दौरान) अद्भुत काम किया।

उन्होंने कहा कि जहां तक पहले इस्तेमाल न करने का सवाल है, भारत ने अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए पहले इस्तेमाल नहीं किया और यह प्रतिबद्धता आगे भी बनी रहेगी।

हालांकि, राजनाथ ने स्पष्ट किया, यह हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन भारत किसी भी तरह की 'परमाणु ब्लैकमेलिंग' स्वीकार नहीं करेगा।

रक्षा मंत्री सोमवार को वियतनाम और दक्षिण कोरिया की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य सैन्य उपकरणों के संयुक्त उत्पादन सहित रणनीतिक रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों का पता लगाना है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने अदाणी के खिलाफ सभी आरोप वापस लिए, मामला स्थायी रूप से बंद

नई दिल्ली/न्यूयॉर्क/भाषा। अमेरिकी न्याय विभाग ने अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से वापस ले लिया है जिससे न्यूयॉर्क में चल रहा बहुचर्चित प्रतिभूति एवं धोखाधड़ी मामला पूरी तरह खत्म हो गया है।

अमेरिकी अभियोजकों ने अदालत में दाखिल दस्तावेज में कहा कि वे अब इन आरोपों को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं।

इसके साथ ही अमेरिका में चल रहे अदाणी समूह से संबंधित सभी मामले पिछले कुछ दिनों में बंद किए जा चुके हैं।

अमेरिकी अभियोजकों ने ईस्टर्न न्यूयॉर्क की अदालत में कहा कि उन्होंने इस मामले की समीक्षा के बाद अपने 'अभियोजन विवेक' के तहत निर्णय लिया है कि वे इन आपराधिक आरोपों पर आगे संसाधन नहीं लगाएंगे।

इसके बाद अदालत ने भी आदेश दिया कि आरोपों को 'स्थायी रूप से खारिज' किया जाए। इसका मतलब है कि यह मामला दोबारा नहीं खोला जा सकता है।

सतीशन के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने ली शपथ

प्रमुख कल्याणकारी कदम उठाने की घोषणा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल में वाम मोर्चे को सत्ता से बेदखल कर 10 साल के बाद फिर से कांग्रेस नीत यूडीएफ की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले वी.डी. सतीशन ने सोमवार को यहां सेंट्रल स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सतीशन के 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल को भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में वरिष्ठ और युवा नेताओं को जगह दी गई है। एक समय मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार माने जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेता राहुल गांधी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता समारोह में मौजूद रहे। यूडीएफ में शामिल अहम सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) को भी मंत्रिमंडल में पर्याप्त जगह मिली और नई सरकार में गठबंधन संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखी।

करीब डेढ़ घंटे तक चले शपथ ग्रहण समारोह और लोक भवन में आयोजित चाय समारोह के बाद राज्य सचिवालय में सतीशन की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में मार्च में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के दौरान राहुल गांधी द्वारा घोषित पांच कार्यक्रमों में से दो को लागू करने का फैसला लिया गया।

इनमें 15 जून से केएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और बुजुर्गों के लिए एक समर्पित विभाग स्थापित किया जाना शामिल है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह विभाग देश में अपनी तरह का पहला विभाग होगा।

चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा घोषित अन्य गारंटियों में कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपए का वजीफा, सामाजिक कल्याण पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए करना, प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और युवा उद्यमियों को पांच लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देना शामिल है।

वाम शासन के दौरान सचिवालय के सामने आशा कार्यकर्ताओं के लंबे आंदोलन के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए यूडीएफ कैबिनेट ने उनके मानदेय में 3,000 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि को भी मंजूरी दी। इसके बाद उनका कुल मासिक मानदेय 12,000 रुपए हो जाएगा।

हालांकि यह यूडीएफ के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे से कम है, लेकिन सतीशन ने कहा कि सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

सतीशन ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय में 1,000 रुपए की वृद्धि करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में खाना बनाने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे और प्री-प्राइमरी शिक्षकों तथा आया के मानदेय में भी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी।

इससे पहले वाम सरकार के दौरान यूडीएफ ने आरोप लगाया था कि राज्य की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है।

इस बारे में सतीशन ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने की हालत पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने 21 और 22 मई को नई विधानसभा का सत्र आहूत करने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की भी घोषणा की, जिसमें विधायकों का शपथ ग्रहण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा।

राज्यपाल का अभिभाषण 29 मई को होगा।

एक अन्य बड़े फैसले में कैबिनेट ने 2023 में अलप्पुझा में नव केरल यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के कथित बंदूकधारी समर्थकों द्वारा दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले की दोबारा जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को मंजूरी दी।

अलप्पुझा से चुनाव जीतने वाले ए डी थॉमस उन युवा कांग्रेस नेताओं में शामिल थे जो इस हमले में घायल हुए थे।

सतीशन ने एसआईटी गठित किए जाने को राजनीतिक प्रतिशोध बताने के आरोप खारिज करते हुए कहा कि सरकार केवल अदालत के निर्देश का पालन कर रही है।

इससे पहले सतीशन ने भगवान के नाम पर शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान जैसे ही उन्होंने अपना पूरा नाम लिया, हजारों समर्थकों ने जोरदार तालियां बजाईं और नारे लगाए।

पूरा शपथ ग्रहण समारोह बेहद उत्साहपूर्ण और जश्न के माहौल में संपन्न हुआ, जो यूडीएफ के ऊंचे मनोबल को दर्शाता था। यूडीएफ ने 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 102 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की है।

अमेरिकी प्रतिबंध छूट से इतर रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा भारत : अधिकारी

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट से इतर भी रूस से तेल खरीदता रहा है और आगे भी व्यावसायिक व्यवहार्यता तथा ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों के आधार पर खरीद जारी रखेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, रूस पर अमेरिकी छूट के संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि हम पहले भी रूस से तेल खरीदते रहे हैं... छूट से पहले भी, छूट के दौरान भी और अब भी खरीदते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के कच्चे तेल खरीदने के फैसले मुख्य रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण और पर्याप्त आपूर्ति उपलब्धता पर आधारित होते हैं।

शर्मा ने कहा, हमारे लिए खरीदारी का आधार मूल रूप से व्यावसायिक समझ है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है और दीर्घकालिक समझौतों के तहत पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। रूसी समुद्री मार्ग से कच्चे तेल की बिक्री और वितरण की अनुमति देने वाली अमेरिकी प्रतिबंधों में अस्थायी छूट 16 मई को समाप्त हो गई।

मुख्यमंत्री नायडू ने शेषाचलम पहाड़ियों में टीटीडी के संरक्षण प्रयासों की सराहना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को शेषाचलम पहाड़ियों में सतत संरक्षण प्रयासों के तहत तिरुमला के 89.4 प्रतिशत क्षेत्र में वन आच्छादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए टीटीडी को बधाई दी।

टीटीडी के अनुसार, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल 2,719 हेक्टेयर में से लगभग 2,431 हेक्टेयर क्षेत्र वनस्पति से आच्छादित है। इस प्रकार नवीनतम 'इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट' (आईएसएफआर) के अनुसार, तिरुमला का 89.4 प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है।

मुख्यमंत्री ने पवित्र पहाड़ी शृंखलाओं में वन संपदा की रक्षा करने और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए मंदिर निकाय के प्रयासों की सराहना की। नायडू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, हमारी परंपराओं में प्रकृति को पवित्र माना जाता है, और जंगलों एवं वन्यजीवों का संरक्षण ईश्वर की सेवा (के समान) है। मैं इन प्रयासों की सराहना करता हूं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरे-भरे और स्वस्थ तिरुमला को संरक्षित करने में मदद करेंगे।

शेषाचलम पहाड़ियों की चोटी पर स्थित तिरुमला, भगवान श्री वेंकटेश्वर का निवास स्थान है।

टीटीडी, तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है, जिसे दुनिया का सबसे धनी हिंदू तीर्थस्थल माना जाता है।

छात्रावास में शराब पीने के बाद अर्धनग्न अवस्था में उत्पात, 50 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों पर जुर्माना

इंदौर (मध्यप्रदेश)/भाषा। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में कथित तौर पर शराब पीने के बाद अर्धनग्न अवस्था में उत्पात और तोड़-फोड़ के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को इंजीनियरिंग के कम से कम 50 विद्यार्थियों पर 25,000-25,000 रुपए का जुर्माना लगाने और उनके परीक्षा परिणाम रोकने का फैसला किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के कुलगुरु राकेश सिंघई ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि छात्रावास में तोड़-फोड़ से सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया, ''घटना में शामिल पाए जाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। जांच पूरी होने तक इन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम रोक दिए गए हैं।''

भाजपा में शामिल होने से इनकार करने पर सिंगला की हुई गिरफ्तारी : केजरीवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला का बचाव करते हुए पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उन्हें भाजपा में शामिल होने से इनकार करने का दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली और गोवा में तलाशी के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सिंगला को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, दीपक सिंगला को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि उसने कोई गलत काम किया है। बल्कि, इसलिए गिरफ्तार किया है, क्योंकि वह भाजपा के खिलाफ काम कर रहे थे और उन्होंने भाजपा में शामिल होने से मना कर दिया। दीपक बहादुर हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के नेता सिंगला और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि दिल्ली और गोवा में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। सिंगला विश्वास नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार थे।

जांच के तहत 2024 में भी ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था। केजरीवाल ने पंजाब के गिरफ्तार हुए मंत्री संजीव अरोड़ा की भी प्रशंसा करते हुए उन्हें बहादुर और देशभक्त बताया। केजरीवाल ने 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में कहा, संजीव जी, आप बहादुर हो। देशभक्त हो। पूरे पंजाब को आप पर गर्व है।

तेलंगाना में 2024-26 के दौरान 820 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण : डीजीपी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सी वी आनंद ने सोमवार को राज्य में माओवादी गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी) द्वारा चलाए जा रहे उग्रवाद-रोधी अभियानों तथा खुफिया उपायों का आकलन किया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, एसआईबी के दौरे के दौरान डीजीपी ने वामपंथी उग्रवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के भूमिगत कैडरों के बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण सुनिश्चित कराने में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निरंतर प्रयासों की सराहना की। विज्ञप्ति में कहा गया कि वर्ष 2024 से 2026 तक कुल 820 माओवादियों ने तेलंगाना पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिनमें माओवादियों की केंद्रीय समिति के चार और राज्य समिति के 22 सदस्य शामिल हैं।

इन आत्मसमर्पणों के दौरान भाकपा (माओवादी) कैडरों ने 334 आग्नेयास्त्र भी जमा कराए, जिनमें 58 एके-47 राइफल, 48 इंसास राइफल, 50 एसएलआर, छह एलएमजी तथा अन्य अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। डीजीपी ने खुफिया आधारित अभियानों, विश्वास बहाली उपायों और पुनर्वास पहलों के माध्यम से तेलंगाना में सशस्त्र माओवादी आंदोलन को कमजोर करने में एसआईबी के उल्लेखनीय योगदान की सराहना भी की। उन्होंने विशेष रूप से भूमिगत माओवादी कैडरों को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में एसआईबी की सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की। डीजीपी आनंद ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास और समाज में उनके पुनर्समावेशन के लिए किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा की और आश्वासन दिया कि तेलंगाना पुलिस उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराती रहेगी। उन्होंने कहा कि एसआईबी को आत्मसमर्पण कर चुके कैडरों पर करीबी नजर रखनी चाहिए तथा उनके कौशल विकास, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, नौकरी उपलब्ध कराने, पुनर्वास और समाज में पुनर्समावेशन को सुनिश्चित करना चाहिए।

रॉयल एनफील्ड 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से आंध्र प्रदेश में लगाएगी नया संयंत्र

मुंबई/भाषा। दोपहिया विनिर्माता रॉयल एनफील्ड ने अपनी विस्तार रणनीति के तहत सोमवार को आंध्र प्रदेश में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से नया विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की। आयशर मोटर्स समूह की कंपनी ने बयान में कहा कि उसने इस संयंत्र के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के ताडा औद्योगिक क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण किया है। इस संयंत्र पर 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। यह परियोजना कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी के अधीन है और इसे भविष्य की मांग एवं बाजार परिस्थितियों के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। चेन्नई स्थित कंपनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 14.6 लाख इकाई प्रति वर्ष है। कंपनी फिलहाल इस क्षमता का लगभग पूरा इस्तेमाल कर रही है। रॉयल एनफील्ड ने फरवरी में तमिलनाडु के चेय्यार में 958 करोड़ रुपए के निवेश से क्षमता विस्तार की घोषणा की थी जिससे कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 20 लाख इकाई प्रतिवर्ष हो जाएगी।

आयशर मोटर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी. गोविंदराजन ने कहा, आंध्र प्रदेश में यह निवेश हमारी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाएगा और अगले चरण की वृद्धि को भी गति देगा। रॉयल एनफील्ड ने कहा कि दीर्घकालिक वृद्धि रणनीति के तहत वह समय-समय पर नए निवेश अवसरों का मूल्यांकन करती रहती है। कंपनी के तमिलनाडु में चार विनिर्माण संयंत्र हैं। इसके अलावा उसकी ब्राजील, बांग्लादेश, नेपाल, थाइलैंड, अर्जेंटीना और कोलंबिया सहित छह देशों में सात सीकेडी इकाइयां तथा ब्रिटेन और चेन्नई में दो तकनीकी केंद्र भी हैं।

आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ का भंडाफोड़, दो सदस्य गिरफ्तार: पंजाब पुलिस

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसने एक आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ का भंडाफोड़ करते हुए इसके दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनसे तीन अवैध हथियार और 11 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनुराज उर्फ गौरव मसीह और अंकुश के रूप में हुई है। दोनों जालंधर के फिल्लौर के निवासी हैं।

पुलिस के अनुसार अंकुश आदतन अपराधी है और इससे पहले भी हत्या के प्रयास के मामले में उसके खिलाफ गोराया थाने में मामला दर्ज किया गया था।

हरियाणा ने नए नियमों को दी मंजूरी

एनसीआर में 'कैब संचालकों' के लिए पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को 'एग्रीगेटर लाइसेंस' देने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कैब सेवाएं देने वाले एग्रीगेटर, डिलिवरी सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में शामिल किए जाने वाले सभी वाहन अनिवार्य रूप से सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), बैटरी चालित वाहन (बीओवी) या अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित होंगे। इसके अलावा, एनसीआर में मौजूदा बेड़े में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक तिपहिया ऑटो-रिक्शा को ही अतिरिक्त रूप से शामिल करने की अनुमति होगी।

राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत एग्रीगेटर लाइसेंस देने संबंधी नियमों को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुरूप दी गई है। सीएक्यूएम ने पिछले वर्ष जून में निर्देश दिया था कि एक जनवरी, 2026 से दिल्ली-एनसीआर में संचालित कैब एग्रीगेटर, डिलिवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में नए पेट्रोल या डीजल वाहन शामिल नहीं किए जाएंगे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्णय स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने और एनसीआर के जिलों में वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। बयान में कहा गया, संशोधित नियमों के तहत एक जनवरी, 2026 से एनसीआर क्षेत्रों में एग्रीगेटर, डिलिवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स इकाइयों के बेड़े में शामिल किए जाने वाले सभी वाहन अनिवार्य रूप से सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), बैटरी चालित वाहन (बीओवी) या अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित होंगे।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 86ए में संशोधन को भी मंजूरी दी, ताकि राज्य में ऐप आधारित यात्री एग्रीगेटर और डिलिवरी सेवा प्रदाताओं के लिए व्यापक नियामकीय ढांचा तैयार किया जा सके। नए प्रावधानों में एग्रीगेटर और डिलिवरी सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस, चालकों और वाहनों के पंजीकरण मानदंड, यात्रियों की सुरक्षा उपाय, शिकायत निवारण प्रणाली, प्रशिक्षण कार्यक्रम, चालकों और यात्रियों के लिए बीमा कवर, ऐप के लिए साइबर सुरक्षा अनुपालन और किराया विनियमन शामिल हैं। मंजूर नियमों के अनुसार, एग्रीगेटर और डिलिवरी सेवा प्रदाताओं को यात्रियों के लिए न्यूनतम पांच लाख रुपए का बीमा कवर, चालकों के लिए कम से कम पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और पंजीकृत चालकों के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए का सावधि बीमा सुनिश्चित करना होगा। नियमों के तहत संबंधित वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, प्राथमिक उपचार किट और अग्निशामक यंत्र लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

'प्रतिचक्रीय पूंजी बफर' व्यवस्था को फिलहाल लागू करने की जरूरत नहीं : आरबीआई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में 'प्रतिचक्रीय पूंजी बफर' (सीसीवाईबी) को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि प्रमुख आर्थिक संकेतकों की समीक्षा और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर फिलहाल यह कदम जरूरी नहीं माना गया है।

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर एक ऐसा अतिरिक्त पूंजी प्रावधान है, जिसे बैंकों को अच्छे आर्थिक दौर में अलग रखना होता है। इसका उद्देश्य है कि भविष्य में आर्थिक स्थिति कमजोर होने की स्थिति में बैंक इस पूंजी के सहारे कर्ज देना जारी रख सकें और अर्थव्यवस्था में नकदी की कमी न आए। आरबीआई के 'वाणिज्यिक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड, 2025' के तहत निर्धारित ढांचे के अनुसार, सीसीवाईबी को जरूरत पड़ने पर लागू किया जाएगा और आमतौर पर इसके फैसले की पहले से घोषणा की जाती है।

इस व्यवस्था में 'ऋण एवं जीडीपी अंतराल' को प्रमुख संकेतक के रूप में देखा जाता है यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले कर्ज कितनी तेजी से बढ़ रहा है। कर्ज के असामान्य रूप से बढ़ने को संभावित जोखिम का संकेत माना जाता है। आरबीआई ने कहा, ''सीसीवाईबी संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर फिलहाल 'प्रतिचक्रीय पूंजी बफर' लागू नहीं करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस व्यवस्था का मकसद एक तरफ बैंकों को अच्छे समय में मजबूत बनाना है, वहीं जरूरत से ज्यादा कर्ज वितरण पर लगाम लगाना भी है। यह ढांचा 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया था।

पांच नाबालिगों ने संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों को जासूसी में मदद की : एनआईए

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने सोमवार को पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकी षड्यंत्र से संबंधित मामले में पांच नाबालिगों के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की। अधिकारियों ने बताया कि इस षड्यंत्र में भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से आरोपियों पर संवेदनशील स्थानों की जासूसी करने का आरोप है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कौशांबी पुलिस थाने में मार्च में दर्ज किए गए जासूसी मामले में अब तक कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों पर रेलवे स्टेशनों के संवेदनशील स्थानों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले कैमरे लगाने और उनसे पाकिस्तान में संदिग्ध आतंकवादियों को सीधे जानकारी उपलब्ध कराने का आरोप है।

मैं माकपा में दरकिनार नहीं, हार के कारणों की समीक्षा करेंगे: शैलजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम/भाषा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की वरिष्ठ नेता के. के. शैलजा ने सोमवार को पार्टी के भीतर उन्हें दरकिनार किए जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वाम दल हाल में हुए केरल विधानसभा चुनाव में अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करेगा।

पार्टी की एक बैठक में भाग लेने के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए केरल सरकार की पूर्व मंत्री ने कहा कि पार्टी इस झटके के कारणों का मूल्यांकन करेगी। पेरावूर से विधानसभा चुनाव हारने वाली शैलजा ने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) कमजोर होने से केरल में सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित हो सकता है। उनका कहना था, यह हमारे लिए एक अप्रत्याशित परिणाम था।'' उन्होंने स्वीकार किया कि एलडीएफ को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि 2021 के चुनाव में इसकी संख्या 99 सीटों से घटकर 2026 में 35 रह गई। उन्होंने कहा, ''हम हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आकलन कर रहे हैं कि क्या बदलाव और सुधार की जरूरत है। मोर्चे का कमजोर होना राज्य के लिए अच्छा नहीं है।'' उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने का बचाव किया। उनके अनुसार, विजयन पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य हैं और इस पद के लिए किसी अन्य नेता के नाम पर विचार नहीं किया जा सकता।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत: एन चंद्रशेखरन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि मजबूत जनसांख्यिकी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और सरकार के सहायक उपायों के दम पर वैश्विक स्तर पर अस्थिर माहौल के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है।

टाटा संस के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य अब तेजी से बदल रहा है, जिससे उच्च अस्थिरता और कम स्पष्टता वाला माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब ऐसे दौर में काम कर रही है, जहां बड़े संरचनात्मक बदलाव, भू-राजनीतिक संवेदनशीलता और तेज प्रौद्योगिकी प्रगति देखने को मिल रही है। उन्होंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीसीपीएल) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा, इन वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत लगातार भरोसेमंद आर्थिक वृद्धि दर्ज कर रहा है। भारत की वृद्धि यात्रा मजबूत जनसांख्यिकीय आधार और तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल सार्वजनिक ढांचे पर आधारित है। उन्होंने कहा कि आयकर में कटौती, ब्याज दरों में कमी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार जैसे सरकारी कदमों से लोगों की खर्च योग्य आय बढ़ी है। वहीं, खासकर खाद्य महंगाई में नरमी और सरकार के लगातार निवेश से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयरधारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इससे भारतीय उपभोक्ता बाजार को मजबूत आधार मिला है, जहां प्रीमियम उत्पादों, स्वास्थ्य एवं कल्याण और डिजिटल माध्यमों से खरीदारी की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री विजय ने अम्मा कैंटीन में स्वादिष्ट, गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को अधिकारियों को राज्य में अम्मा कैंटीन के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और लोगों को स्वादिष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करने का निर्देश दिया।

अम्मा कैंटीन में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वाद संतोषजनक नहीं होने की शिकायतें मिलने के बाद, मुख्यमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने सुविधाओं, बुनियादी ढांचे में सुधार करने, अधिक खाना पकाने के बर्तन/उपकरण खरीदने और लोगों को गुणवत्तापूर्ण एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करने के आदेश दिए।

वृहद चेन्नई नगर निगम के अंतर्गत 383 अम्मा कैंटीन और राज्य में अन्य स्थानीय निकायों के तहत 237 कैंटीन हैं। अम्मा कैंटीन की शुरुआत अन्नाद्रमुक के शासनकाल (2011-16) में हुई थी और इसका नाम तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता के नाम पर रखा गया था, जिन्हें उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता प्यार से ''अम्मा'' कहा करते थे। अम्मा कैंटीन में भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के 22 मई को नई दिल्ली दौरे पर जाने की संभावना

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के 22 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के लिए राष्ट्रीय राजधानी का दौरा करने की उम्मीद है। एक सूत्र ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री के रूप में अपनी तीन दिवसीय पहली यात्रा के दौरान, विजय के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने और श्रीलंका के तटरक्षक बल द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों पर लगातार हमले किए जाने का मुद्दा उठाने की भी उम्मीद है।

उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने की भी संभावना है। बैठक के दौरान, वह कई विकास संबंधी मुद्दों के लिए केंद्रीय सहायता का अनुरोध करते हुए एक प्रस्तुति देंगे।

अन्नाद्रमुक के गुट शक्ति प्रदर्शन में जुटे, पलानीस्वामी ने पार्टी के जिला सचिवों की बैठक बुलाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के गुट शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं जिसका मकसद खुद को प्रबल दिखाकर पार्टी पर नियंत्रण स्थापित करना है। दोनों गुटों के बीच बढ़ते मतभेदों की पृष्ठभूमि में अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के प्रयास में मंगलवार को अपने ग्रीनवेज स्थित आवास पर पार्टी के जिला सचिवों की बैठक बुलाई है। पार्टी के एक सूत्र ने जानकारी दी।

पलानीस्वामी को पूर्व राज्य मंत्रियों सी वे षणमुगम और एस पी वेलुमणि के खुले विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। षणमुगम और वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट ने 23 पार्टी विधायकों के साथ 13 मई को सदन में शक्ति परीक्षण के दौरान टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया था और पलानीस्वामी के टीवीके के खिलाफ मतदान करने के निर्देश का उल्लंघन किया था। षणमुगम और वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी सदस्यों के बीच सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था 'आम परिषद' की बैठक को बुलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। अन्नाद्रमुक ने 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अभी तक कोई बैठक नहीं बुलाई है, जिसमें उसे केवल 47 सीटें ही मिली हैं। पत्रकारों से बातचीत में पलानीस्वामी का समर्थन कर रहे एस एस कृष्णमूर्ति ने कहा कि जिला सचिव पलानीस्वामी के साथ मजबूती से खड़े हैं।

पूर्व राज्य मंत्री डॉ. सी. विजयभास्कर, जो षणमुगम गुट के लिए समर्थन जुटा रहे हैं, ने कहा कि अन्नाद्रमुक पार्टी के नियमों के अनुसार, पार्टी की आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त संख्या में सदस्यों ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा, ''सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र पलानीस्वामी को सौंपे जाएंगे, जिसमें उनसे आम परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह किया जाएगा।'' पूर्व राज्य मंत्री दिंडीगुल सी. श्रीनिवासन ने कहा कि पार्टी में बहुमत उनके वर्तमान महासचिव का समर्थन करता है।

द्रमुक के समर्थन से अन्नाद्रमुक के सरकार बनाने की झूठी खबर फैलाई जा रही : ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने सोमवार को कहा कि यह ''झूठी खबर'' फैलाई जा रही है कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के समर्थन से उनकी पार्टी सरकार बनाने की योजना बना रही है। पलानीस्वामी ने रेखांकित किया कि अन्नाद्रमुक की स्थापना 1972 में द्रमुक के विरोध के सिद्धांत पर हुई थी और यह फर्जी खबर फैलाई जा रही है कि उनकी पार्टी द्रमुक के समर्थन से सरकार बनाने की योजना बना रही है।

अन्नाद्रमुक विधायक अंबालगन ने पुडुचेरी विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुडुचेरी/भाषा। 'ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम' (अन्नाद्रमुक) के विधायक ए. अंबालगन ने सोमवार को लोक निवास में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में पुडुचेरी विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने तमिल भाषा में अंबालगन को शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री एन रंगासामी, भाजपा नेता ए नमस्सिवायम, यनम से एक अन्य मंत्री एवं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के नेता मल्लाडी कृष्णा राव, विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों और मुख्य सचिव शरत चौहान समेत कई लोगों ने अंबालगन को अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अंबालगन 20 मई को सदन में नवनिर्वाचित सभी विधायकों को पद की शपथ दिलाएंगे ताकि वे आधिकारिक तौर पर पुडुचेरी की 16वीं विधानसभा के सदस्य बन जाएं। अंबालगन पुडुचेरी की उप्पलम विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अंबालगन ने कहा कि राज्य विधानसभा की बैठक 20 मई को होगी और सभी नवनिर्वाचित विधायकों को उसी दिन सदन में पद की शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह समारोह 20 मई को विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारित किया जाएगा।

अन्नाद्रमुक, एआईएनआरसी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा है और समझौते के तहत उसे दो सीट मिली थीं। नौ अप्रैल के चुनाव में वह ऑर्लेनपेठ सीट से हार गई। राजग ने नौ अप्रैल को हुए चुनावों में इस केंद्रशासित प्रदेश में जीत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी थी।

तमिलनाडु में 10 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 से अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवा (भाप्रसे) के अधिकारियों के तबादले कर दिये।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, गगनदीप सिंह बेदी को नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पी. अमुधा सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव का पदभार संभालेंगी। सत्यव्रत साहू का तबादला कर उन्हें जल संसाधन विभाग में सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। शुचोंगम जातक चिरु को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का सचिव और अनिल मेश्राम को ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। एम. वल्लार परिवहन विभाग के सचिव होंगे और के. एस. पलानीसामी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का जिम्मा संभालेंगे।

इसी तरह, वी. दक्षिणामूर्ति को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। सज्जनसिंह आर. चव्हाण को युवा कल्याण और खेल विकास विभाग का सचिव तथा प्रशांत एम. वडनेरे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

जी. के. अरुण सुंदर थयालन पंजीकरण महानिरीक्षक का पदभार संभालेंगे और जी. लक्ष्मीपति वित्त विभाग के संयुक्त सचिव होंगे।

विज्ञप्ति में बताया गया कि टी. आनंद की सेवाएं चेन्नई शहरी जलापूर्ति तथा मल-जल निकासी बोर्ड को सौंप दी गई हैं, जहां उन्हें प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता सेम्मलाई ने पार्टी से इस्तीफा दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के वरिष्ठ नेता एस. सेम्मलाई ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सेम्मलाई ने दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निधन के बाद पार्टी में बढ़ती आंतरिक कलह व अवसरों की कमी पर गहरी निराशा जताई। सेम्मलाई ने अपने त्यागपत्र में पार्टी के हाल के घटनाक्रमों पर निराशा जतायी।

त्यागपत्र में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए सेम्मलाई ने लिखा, ''चुनाव के बाद अन्नाद्रमुक में जो कुछ घटनाक्रम देखने को मिला, उससे मुझे गहरा दुख हुआ है। यही भावना उन लाखों कार्यकर्ताओं की भी है, जिन्होंने अपना जीवन इस आंदोलन को समर्पित कर दिया।'' उन्होंने कहा, ''जो घटनाक्रम हुआ या हो रहा है, उनमें से कोई भी संतोषजनक नहीं है।'' वरिष्ठ नेता ने सवाल किया, ''क्या यही उस आंदोलन की नियति है, जिसे क्रांतिकारी नेता एमजीआर ने खड़ा किया और अम्मा (जयललिता) ने सींचा?'' उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि मीडिया की खबरों में भी आंतरिक कलह पर उपहास उड़ाया जा रहा है। सेम्मलाई ने आरोप लगाया कि जयललिता के निधन के बाद उन्हें किनारे कर दिया गया। उन्होंने कहा, ''मेरे लिए बाधाएं खड़ी की गईं लेकिन मैं अपनी भावनाएं व्यक्त किए बिना चुपचाप काम करता रहा।'' उन्होंने कहा,''मौजूदा हालात में मेरा मन इस आंदोलन में बने रहने की इजाजत नहीं देता।''

सेम्मलाई ने यह भी याद किया कि पार्टी के दिवंगत संस्थापक एमजीआर और जयललिता ने उन्हें अनेक अवसर दिए और उन्हें ''राजनीतिक क्षेत्र में एक चमकते सितारे'' के रूप में उभरने में मदद की। उन्होंने कहा, ''भारी मन से मैंने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है।''

विधानसभा चुनाव में हार के बाद पलानीवेल त्यागराजन ने सक्रिय राजनीति से बनाई दूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में अपनी हार के बाद, सोमवार को सक्रिय सार्वजनिक जीवन से कुछ समय के लिए दूरी बनाने की घोषणा की।

राजन ने मदुरै सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि वह इस विराम अवधि का उपयोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यान देने और 'हार्परकॉलिन्स' द्वारा प्रकाशित होने वाली अपनी आगामी पुस्तक को पूरा करने के लिए करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु की राजनीति ने निश्चित रूप से एक नए युग में प्रवेश कर लिया है।

सोशल मीडिया पर जारी एक विस्तृत बयान में राजन ने एक दशक की जनसेवा को याद करते हुए कहा कि इस विश्राम से उन्हें अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में पूर्व-निर्धारित अंतरराष्ट्रीय व्याख्यानों को संबोधित करने का अवसर मिलेगा, जिनकी अनुमति उन्हें मंत्री पद पर रहने के दौरान नहीं मिल पाई थी।

'तमिलगा वेत्री कषगम' (टीवीके) के उम्मीदवार से अपनी हार स्वीकार करते हुए पूर्व वित्त एवं आईटी मंत्री ने कहा कि जनसेवा के प्रति उनका जज्बा कम नहीं हुआ है।

अनाइमंगलम चोल काल के ताम्रपत्रों के तमिलनाडु में सार्वजनिक प्रदर्शन की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु में कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने मांग की है कि अनाइमंगलम चोल काल के ताम्रपत्रों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए राज्य में लाया जाए।

ये ताम्रपत्र राजेंद्र चोल प्रथम के काल से संबंधित हैं और मूल रूप से उनके पिता राज राजा चोल प्रथम द्वारा जारी किया गया एक फरमान है। इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हेग की उनकी यात्रा के दौरान भेंट किया गया था। नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय पुस्तकालय ने 16 मई को 11वीं शताब्दी के चोलकालीन ताम्रपत्र लौटाए, जिन पर तमिल और संस्कृत में पाठ हैं। 21 बड़े पत्रों और तीन छोटे पत्रों का यह सेट 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान चोल राजाओं द्वारा जारी किए गए शाही दस्तावेज हैं, जो राज्य के नागपट्टिनम में स्थित चुलमणिवर्मा-विहार नामक एक बुद्ध विहार को अनाइमंगलम गांव के उपहार स्वरूप दिए जाने को औपचारिक रूप देते हैं। एमडीएमके के महासचिव वाइको ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि ताम्रपत्रों को संरक्षित किया जाए और नागपट्टिनम संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाए। वाइको ने रविवार को यहां एक बयान में कहा, कुलथुंगा चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान जारी किये गए इन पत्रों ने एक बौद्ध विहार, एक मठ को पहले दिए गए अनुदानों की पुष्टि की। इतिहासकार इन पत्रों को महज प्रशासनिक अभिलेख नहीं मानते, बल्कि इन्हें मध्यकालीन दक्षिण भारत के तमिलनाडु के बहुसांस्कृतिक स्वरूप और व्यापक समुद्री व्यापार संबंधों के महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में वर्णित करते हैं।

माकपा के लोकसभा सदस्य सु वेंकटेशन ने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों से 654 प्राचीन वस्तुएं भारत वापस लाई गई हैं और उन्हें नई दिल्ली स्थित पुराना किला में रखा गया है। उन्होंने एक बयान में कहा, लेकिन ये लोगों के देखने के लिए प्रदर्शित नहीं हैं। अनाइमंगलम के ताम्रपत्रों का भी यही हाल हो सकता है। इसलिए, इन्हें तमिलनाडु लाया जाना चाहिए और राज्य के पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए। गंगईकोंडा चोलपुरम विकास परिषद के अध्यक्ष आर. कोमागम ने कहा कि अनाइमंगलम के ताम्रपत्रों को गंगईकोंडा चोलपुरम लाया जाना चाहिए जो राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल से लगभग तीन शताब्दियों तक चोल राजवंश की राजधानी थी और उन्हें स्थायी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाना चाहिए। पुरातत्व और तमिल संस्कृति के पूर्व मंत्री थंगम थेनारसु ने कहा कि इन ताम्रपत्रों को तमिलनाडु में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका इतिहास वास्तव में तमिलनाडु से संबंधित है।

अनाइमंगलम गांव नागपट्टिनम जिले के किलवेलूर में स्थित है और जिला मुख्यालय से लगभग 19 किलोमीटर दूर है।

तमिलनाडु में खेल क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी: मंत्री आधव अर्जुन

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन ने सोमवार को कहा कि खेल क्षेत्र को बढ़ावा देना तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने यहां नेहरू स्टेडियम का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से कहा, ''मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाएं बना रहे हैं। इस पहल के तहत राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।''

मंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी स्तरों पर खेलों को प्राथमिकता देकर तथा इस तरह की कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए मादक पदार्थों के बढ़ते चलन को जड़ से खत्म करने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, ''हमने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य शुरू कर दिए हैं।'' उन्होंने कहा कि सभी जिलों में खेल क्षेत्र के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा सुविधाओं को उन्नत करने के मकसद से आवश्यक उपाय किए जाएंगे। मंत्री ने कहा, ''बेहतर समाज के निर्माण में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह युवाओं को अपने स्कूली जीवन से ही मादक पदार्थों का शिकार होने से बचाता है और शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है।''

केरल की जनता की आवाज नई सरकार का मार्गदर्शन करेगी : राहुल

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केरल की नई सरकार को बधाई दी और कहा कि जनता की आवाज इसका मार्गदर्शन करेगी तथा काम की शुरुआत तत्काल हो रही है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री और 20 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली।

राहुल गांधी ने पोस्ट किया, ''केरल के लोगों ने इस सरकार के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी आवाज़ इसका मार्गदर्शन करेगी। वी.डी. सतीशन को हार्दिक बधाई। सतीशन जी के साथ ही पूरी कैबिनेट, अब हर केरलवासी की आवाज का प्रतिनिधित्व करेगी। के.सी. वेणुगोपाल जी को धन्यवाद, जिन्होंने आगे बढ़कर इस अभियान का नेतृत्व किया।'' उनका कहना था, ''यह जीत प्रत्येक यूडीएफ कार्यकर्ता और डिजिटल योद्धा की है जिन्होंने इस अभियान के दौरान अथक प्रयास किया। काम की शुरुआत अभी से हो रही है।'' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पोस्ट किया, ''मैं केरल में नई कांग्रेस-यूडीएफ सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस-यूडीएफ के सामूहिक नेतृत्व में केरल अब सच्ची प्रगति और भविष्य-आधारित विकास का गवाह बनेगा।''

राधाकृष्णन ने केरल विधानसभा की कार्यवाही में गरिमा और एकजुटता पर दिया जोर

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल विधानसभा के नामित विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थिरुवंचूर राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि जनहित का कोई भी मुद्दा उठाते समय सदन में गरिमा और शालीनता बनाए रखी जानी चाहिए। साथ ही राधाकृष्णन ने कहा कि विधानसभा अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बल प्रयोग या डंडे का इस्तेमाल करने की जगह नहीं है; बल्कि यह प्रेम और एकजुटता पर आधारित भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देने का एक मंच है। उन्होंने बातचीत में कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की गरिमा बनाए रखने में सभी लोग सहयोग करेंगे।

केरल में कांग्रेस नेतृत्व ने मुस्लिम लीग और जमात-ए-इस्लामी के आगे घुटने टेक दिए हैं: भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भाजपा ने सोमवार को वी.डी. सतीशन के केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस्लामी कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए तथा वह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और जमात-ए-इस्लामी के दबाव में काम कर रही है। केरल में वी.डी. सतीशन ने सोमवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यहां कांग्रेस विधायक दल के नेता को पद की शपथ दिलाई।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन में कांग्रेस नेतृत्व ने अपने विधायकों की अपेक्षाओं को नजरअंदाज किया। पूनावाला ने 'एक्स' पर तंज कसते हुए पोस्ट किया, ''जमात और आईयूएमएल के पहले मुख्यमंत्री श्री वी.डी. सतीशन को बधाई।'' आईयूएमएल केरल में कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है। वीडियो बयान के साथ पोस्ट साझा करते हुए भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आलाकमान ने ''वोट बैंक की राजनीति'' के लिए मुस्लिम लीग और जमात-ए-इस्लामी की मांगों के आगे ''घुटने टेक दिए।'' उन्होंने दावा किया, ''जैसे ही मुस्लिम लीग और जमात के दबाव में कांग्रेस ने सतीशन को चुना, मुस्लिम लीग अपने असली रंग दिखाने लगी।'' पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि केरल में कांग्रेस की सरकार असल में मुस्लिम लीग चला रही है। उन्होंने कहा, ''यह कांग्रेस की सरकार नहीं, मुस्लिम लीग की सरकार है।'' उन्होंने कांग्रेस पर ''इस्लामी कट्टरपंथियों'' से हाथ मिलाने का आरोप भी लगाया। भाजपा नेता ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के चयन में कांग्रेस विधायकों की लोकतांत्रिक इच्छा को ''दरकिनार'' कर दिया गया।

मुख्यमंत्री सतीशन ने शपथ ग्रहण समारोह में प्रोटोकॉल के उल्लंघन का बचाव किया

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशान ने सोमवार को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रोटोकॉल के उल्लंघन का बचाव करते हुए कहा कि परंपराओं और रिवाजों का बदलना स्वाभाविक है। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह को उन लोगों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम बताया, जिन्होंने सरकार को चुना है।

समारोह के दौरान मंच पर गणमान्य व्यक्तियों के बैठने के बारे में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए सतीशन ने कहा कि कार्यक्रम में जितने लोग शामिल हुए, उन सभी का ख्याल रखा जाना था।

ऐसी खबरें थीं कि लोक भवन ने निर्देश दिया था कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंच पर केवल प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, परंपराओं और रिवाजों का बदलना स्वाभाविक है। किसी चीज को 100 या 150 वर्षों के लिए स्थापित परंपरा या रिवाज के रूप में मानना उचित नहीं है। सतीशन ने कहा कि इस समारोह में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए।

सतीशन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (जिन्हें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था) ने भी समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि नेमोम से विधायक चुने गए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, माकपा के प्रदेश सचिव बिनॉय विश्वम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी भीड़ की आशंका थी और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता ने चुना था और शपथ ग्रहण समारोह सभी की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

तमिलनाडु के जंगल में तेंदुआ मृत पाया गया

नीलगिरी/भाषा। नीलगिरी जिले के गुडालूर वन प्रभाग के अंतर्गत मेफील्ड एस्टेट के पास सोमवार को एक वयस्क तेंदुआ मृत पाया गया। वन अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के दिशानिर्देशों के अनुसार, मृत तेंदुए का गुडालूर वन प्रभाग के पशु चिकित्सक पोस्टमार्टम करेंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जानवर की मौत का सही कारण प्रयोगशाला रिपोर्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगा।

जनता और सरकार के बीच संवाद का माध्यम बन रही जनसुनवाई : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने आवास पर जनसुनवाई आयोजित की, जहां उन्होंने राज्यभर से आए लोगों की शिकायतें सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया। एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है। बयान में कहा गया है कि जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और अन्य नागरिकों से बातचीत की और अधिकारियों को उनकी शिकायतें तुरंत निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की जनसुनवाई सरकार और जनता के बीच संवाद और विश्वास को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। अच्छे शासन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

कांग्रेस का नीट पेपर लीक पर विरोध, 21 मई को भाजपा कार्यालय का करेंगे घेराव

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को नीट-2026 पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे एवं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को भंग करने की मांग की। कांग्रेस ने बताया कि यह विरोध 21 मई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में होगा। पार्टी कार्यकर्ता जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय का घेराव करेंगे।कांग्रेस के प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है और इससे केंद्र सरकार एवं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की गंभीर लापरवाहियां उजागर हुई हैं। उन्होंने इसमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता का भी आरोप लगाया और कहा कि पिछले वर्षों में भी ऐसे पेपर लीक हुए, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं की गई।चतुर्वेदी ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह पार्टी मुख्यालय पर एकत्र होंगे और शहीद स्मारक होते हुए भाजपा कार्यालय तक मार्च करेंगे, जहां वे प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

राजस्थान में भीषण गर्मी, बाड़मेर में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा

जयपुर। राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में बाड़मेर सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, इस सप्ताह राज्यभर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में लू जैसी स्थिति रहने का अनुमान है। विभाग ने अगले चार से पांच दिनों तक पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में 2030 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने का पूर्वानुमान जताया है। प्रशासन ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान के अधिक रहने की संभावना है।

विधानसभा का प्रतीक चिन्ह राजस्थान की संस्कृति का द्योतक : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष पर विधान सभा के प्रतीक चिन्ह का विमोचन और विधानसभा के 13 द्वारों के नामकरण पट्टिका का अनावरण कर अमृत महोत्सव का उद्घोष किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र सदन है। राजस्थान विधानसभा का गौरवमय इतिहास रहा है। स्वतंत्र भारत में भले ही 1952 में विधानसभा गठित हुई परन्तु राजस्थान में 1913 में स्वतंत्रता से पूर्व ही महाराजा गंगा सिंह ने प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर विधानसभा की शुरुआत कर दी थी। विधान सभा के अमृतकाल के अवसर पर प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण महत्वपूर्ण हैं।

राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की पहल पर तैयार लोगो राजस्थान के जन मानस की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने प्रतीक चिन्ह में सम्मिलित राज्य वृक्ष खेजड़ी और विधान सभा भवन की छवियों की चर्चा करते हुए कहा कि यह राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी उत्सवधर्मिता से जीवन जीने वाले लोगों की जीवटता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि खेजड़ी तो राजस्थान का कल्प वृक्ष है। खेजड़ी के लिए हुए बलिदान की वृक्ष संस्कृति की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऊँट और गोडावन का समावेश समन्वय की संस्कृति का द्योतक है।

राज्यपाल ने भारत की पहली लोक सभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर की चर्चा करते हुए कहा कि एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूं। आपको प्रबंध से जुडी विशेषज्ञता चाहिए तो बताएं। मावलंकर ने देखा कि उसने आवश्यकता से अधिक भोजन थाली में लिया और खाने के पश्चात उसमें से भी बहुत सारा छोड़ दिया। वह बोले तुम अपने भोजन का प्रबंध तो ठीक से कर नहीं सकते फिर दूसरा प्रबंध कैसे करोगे। बागड़े ने कहा कि जीवन में आदर्श आचरण के साथ सभी चीजों का प्रबंधन व्यवहार में आना जरूरी है। उन्होंने पिछड़े और गरीब लोगों की शिक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया।

राज्यपाल ने कहा कि देश शिक्षा से ही आगे बढता है। बच्चों का टेलेंट प्रगति में सहयोगी होता है। शिक्षा को व्यवहार में लाने की जरूरत है। सभी स्कूल अच्छे कैसे हों, वहां व्यवहारिक शिक्षा कैसे मिले, इस पर सभी मिलकर सोचे। राज्यपाल ने महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष रहने के अपने संस्मरण भी साझा किए और कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम अधिकारों के साथ कर्तव्य के प्रति भी सजग रहें। उन्होंने विधानसभा द्वारों के नामकरण के अंतर्गत राजस्थान की शौर्य और वीरता की धरती से जुड़े स्थानों के समावेश की सराहना की।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा के अमृतकाल में हमारा सकंल्प और भावी दृष्टिकोण जनता का अटूट विश्वास है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान विधान सभा देश की ऐसी विधान सभा बन गई है, जिसका प्रतीक चिन्ह (लोगो) बनाया गया है। लोकतंत्र, जनविश्वास और संवैधानिक मर्यादाओं की सतत साधना के गौरवपूर्ण इतिहास की साक्षी राजस्थान विधान सभा ने राजपूताना की रियासतों से निकलकर आधुनिक राजस्थान के निर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और जनप्रतिनिधित्व की परंपरा को सशक्त बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

कोटा के सरकारी अस्पताल में सर्जरी के बाद की जटिलताओं के कारण गर्भवती महिला की मौत

पिछले सप्ताह अस्पताल में शिरीन की गर्भाशय की साधारण सर्जरी हुई थी और बाद में परिवार की मांग पर उसे सरकारी अस्पताल से उनकी पसंद के स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया गया था।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोटा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) में रविवार दोपहर सर्जरी के बाद उत्पन्न जटिलताओं के कारण पांच महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शिरीन (20) पांच महीने की गर्भवती थी और छह मई को उसकी गर्भाशय की साधारण सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे पेशाब संबंधी जटिलताएं होने लगीं।

अधिकारियों के मुताबिक, बाद में शिरीन को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और शनिवार को फिर से एनएमसीएच लाया गया, जहां रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे उसकी मौत हो गई। इससे पहले, पिछले हफ्ते कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल और एनएमसीएच में सिजेरियन प्रसव के बाद की जटिलताओं के कारण चार महिलाओं की मौत हो गई थी। ताजा मामले के साथ इस तरह हुई मौतों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है।

इस बीच, एनएमसीएच के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में पांच अन्य महिलाओं की हालत स्थिर बताई गई है, जबकि एक महिला को स्वस्थ होने के बाद इस सप्ताह पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। परिजन ने आरोप लगाया कि एनएमसीएच के चिकित्सकों ने उन्हें उसी दिन शिरीन को निजी अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर किया था, जिसके बाद वे उसे निजी अस्पताल ले गए।

शिरीन के चाचा मोहम्मद एजाज ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से मुफ्त आईसीयू और जांच सुविधा के निर्देश होने के बावजूद परिवार ने निजी अस्पताल में इलाज और दवाओं पर करीब चार लाख रुपये खर्च किए। एजाज ने बताया कि शनिवार को परिवार ने शिरीन को फिर से निजी अस्पताल से एनएमसीएच लाने का फैसला किया, लेकिन रविवार को उसकी मौत हो गई।

एजाज ने आरोप लगाया कि पिछले सप्ताह मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने परिवार पर शिरीन को निजी अस्पताल ले जाने का दबाव बनाया था। एनएमसीएच के अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. आरपी मीणा ने कहा कि गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखी गई शिरीन को शनिवार को निजी अस्पताल से लाया गया था और रविवार दोपहर उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह अस्पताल में शिरीन की गर्भाशय की साधारण सर्जरी हुई थी और बाद में परिवार की मांग पर उसे सरकारी अस्पताल से उनकी पसंद के स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया गया था। डॉ. मीणा ने बताया कि शनिवार को परिवार ने शिरीन को फिर से एनएमसीएच में भर्ती करा दिया।

प्रदेश में 56 हजार वरिष्ठजन करेंगे तीर्थ दर्शन

जयपुर। प्रदेश सरकार के देवस्थान विभाग की महत्वपूर्ण वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना - 2026 के तहत 50 हजार को रेल एवं 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से निःशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा। देवस्थान विभाग आयुक्त लक्ष्मी नारायण मंत्री के अनुसार उक्त यात्रा के संबंध में विभाग द्वारा शीघ्र नवीन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट http://devasthan.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रदान की जाएगी। देवस्थान आयुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार की बजट घोषणा के तहत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना - 2026 के लिए प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों को देश में सुप्रसिद्ध 15 जन आस्था के तीर्थ स्थलों पर रेल व हवाई मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि हवाई मार्ग द्वारा तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल की निःशुल्क यात्रा का प्रावधान है।

अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान गितेश मालवीया ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक आवेदन स्वयं एवं ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं।

मरीजों को गर्मी में राहत देने के लिए व्यवस्थाएं और सुढ़ करने के शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने दिए निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने सोमवार को मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर का औचक निरीक्षण कर विभिन्न चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपचार व्यवस्था, ट्रॉमा सेवाओं, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं तथा मरीजों एवं उनके परिजनों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्रीमती राठौड़ ने ट्रॉमा सेंटर, सीटी स्कैन एवं एक्स-रे विंग, ओपीडी सेक्शन, आपातकालीन विभाग, आईसीयू-डी रेड जोन, ट्रॉमा कैजुअल्टी वार्ड तथा मल्टी लेवल आईसीयू वार्ड का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न इकाइयों में व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए उपचाराधीन मरीजों एवं उनके परिजनों से संवाद कर उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाओं, उपचार व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान श्रीमती राठौड़ ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि भीषण गर्मी को देखते हुए मरीजों एवं उनके साथ आने वाले परिजनों को अधिकतम राहत उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने अस्पताल परिसर में कूलिंग सिस्टम, छायादार टेंट, पेयजल एवं बैठने की पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी मरीज को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ओपीडी एवं पंजीयन व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए श्रीमती राठौड़ ने मरीजों के रजिस्ट्रेशन एवं पर्ची बनवाने में लगने वाले समय की जानकारी ली। उन्होंने आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त काउंटर संचालित करने तथा भीड़ प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध हो । ट्रॉमा सेंटर निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव ने ट्रॉमा प्रबंधन एवं आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एमडीएम अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रॉमा केस पहुंच रहे हैं, ऐसे में ट्रॉमा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने, मैनपावर की प्रभावी तैनाती तथा लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करने की दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत चिकित्सा संरचना को और मजबूत किया जाए ताकि मरीजों को बेहतर एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध हो सके।

निरीक्षण के उपरांत मीडिया से संवाद करते हुए श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में आने वाले प्रत्येक मरीज को निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, एवं निःशुल्क ऑपरेशन उपलब्ध करवाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर मरीज को सुविधा उपलब्ध नहीं होने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों को आवश्यकता अनुसार स्पॉट परचेज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि आपात परिस्थितियों में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा मरीजों पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़े।

जयपुर जिले के विधायक एवं जनप्रतिधियों की मौजूदगी में हुई बैठक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर जिला कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह, जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा, दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा एवं सीकर सांसद अमराराम की मौजूदगी में आयोजित हुई बैठक में जिले में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सहित जनहित से जुड़े अहम बिन्दुओं पर चर्चा हुई। जयपुर सांसद ने कहा कि पेयजल आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जयपुर शहर में पेयजल की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जलदाय विभाग को दिए हैं। उन्होंने आगामी 15 दिवस में जयपुर जिले में बेहतर पेयजल व्यवस्था हेतु स्वीकृत एमपी एमएलए लेड के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रदान किए हैं। उन्होंने एक सप्ताह उपरांत जयपुर जिले की पेयजल समस्याओं के निराकरण के संबंध में पुनः बैठक आयोजित करने के निर्देश जिला कलक्टर जयपुर को दिए। उन्होंने मानसून से पूर्व शहर के सभी नाले-नालियों की सफाई प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए हैं ताकि वर्षा के दौरान जलभराव के कारण आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ प्रदान कराने के लिए वार्ड अनुसार शिविर लगाकर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने जयपुर के मध्य से गुजरने वाली द्रव्यवती नदी का उचित विकास व सौंदर्यीकरण कराकर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

जयपुर सांसद ने जयपुर शहर के शमशान स्थलों विशेष रूप से चांदपोल मोक्षधाम पर शवयात्रा में आने वाले व्यक्तियों के लिए धूप व बारिश से बचाव के लिए छाया के साथ-साथ बैठने की उचित व्यवस्था करने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मुहाना कृषि उपज मण्डी में प्रतिदिन आने वाले किसानों के लिए सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ नियमित रूप से साफ-सफाई, फल सब्जियों के कचरे का समुचित निस्तारण के साथ-साथ सौंदर्यीकरण के कार्य करवाने के निर्देश भी प्रदान किए हैं।

देश के पहले आरआरटीएस नेटवर्क से जुड़ेगा राजस्थान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता से राजस्थान को नई दिल्ली से तेज, सुरक्षित और विश्वस्तरीय परिवहन नेटवर्क के जरिए जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना को नई गति मिली है। राज्य सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनने से अब आने वाले समय में राजस्थान नमो भारत नेटवर्क से जुड़ेगा और दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन संभव हो सकेगा। नई दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होने वाला दिल्ली-गुरुग्राम - एसएनबी-अलवर कॉरिडोर मुनिरका, एरोसिटी, गुरुग्राम, बावल होते हुए एसएनबी से खैरथल एवं अलवर तक पहुंचेगा। वहीं, एसएनबी से इसका दूसरा हिस्सा नीमराणा, बहरोड़ होते हुए सोतानाला तक विस्तारित होगा। इससे राजस्थान के भिवाड़ी एवं नीमराना सहित एनसीआर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा तथा निवेश व रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए तैयार 'एकीकृत परिवहन योजना' के तहत क्षेत्र के प्रमुख शहरों को आधुनिक एवं तीव्र परिवहन प्रणाली से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर तथा दिल्ली-पानीपत- करनाल कॉरिडोर को नमो भारत कॉरिडोर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन कॉरिडोर्स में से दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर का लोकार्पण भी हो चुका है। इस पूरी परियोजना के अन्तर्गत कुल 196 किलोमीटर लंबा नमो भारत नेटवर्क एवं 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई मजबूती प्रदान करेंगे। राजस्थान में इस परियोजना की कुल लंबाई 91 किलोमीटर होगी और इसमें 6 स्टेशन प्रस्तावित हैं।

यह नेटवर्क 160 किलोमीटर प्रति घंटा की उच्च गति जैसी सुविधाओं से लैस होगा। नमो भारत नेटवर्क के तीनों कॉरिडोर्स को इंटर-ऑपरेबल भी बनाया जा रहा है, जिससे यात्री एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर तक निर्बाध और त्वरित यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन पर ये कॉरिडोर्स परस्पर जुड़ेंगे। आरआरटीएस ट्रेनों का संचालन डेडिकेटेड एवं एलिवेटेड कॉरिडोर पर किया जाएगा, जिससे यह सड़क यातायात और जाम से पूरी तरह मुक्त रहेगा।

साथ ही, इस पूरे नेटवर्क को रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल (आईएसबीटी), एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो से जोड़ा जाएगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) सार्वजनिक परिवहन का एक अत्याधुनिक मॉडल है, जिसे विशेष रूप से एनसीआर क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इसकी ट्रेनें मेट्रो की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक गति से संचालित होती है। जहां मेट्रो मुख्यतः एक शहर के भीतर यात्रा का माध्यम है, वहीं आरआरटीएस निटकवर्ती शहरों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से जोड़ने का कार्य करती है।

हरियाणा और राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरने वाला दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर कॉरिडोर न केवल एनसीआर क्षेत्र में आवागमन को तेज एवं सुगम बनाएगा, बल्कि राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं आधारभूत संरचना के विस्तार के नये युग का सूत्रधार बनेगा।

ऊर्जा एवं टोंक जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने देवली में दिव्यांगों को दी स्कूटी की सौगात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर, 18 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला, श्रमिक, युवा, किसानों को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।

नागर सोमवार को टोंक जिले की देवली नगर पालिका परिसर में दिव्यांगजनों के स्कूटी वितरण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। हमारी सरकार ने हाल ही में ग्राम विकास रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लेकर आमजन को जागरुक करने का कार्य किया, ताकि एक भी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित नही रहें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार के विधायक कोष से स्थानीय विधायक राजेन्द्र गुर्जर द्वारा आप सभी को 59 स्कूटियों का वितरण किया जा रहा है। आपके विधायक आमजन की व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग भाई-बहिनों को स्कूटी मिलने से उनका जीवन सुगम हो सकेगा। उन्हें रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना नही करना पड़ेगा।

नागर ने कहा कि जनहितैषी योजनाओं को लेकर राज्य सरकार वंचित वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खाद्य सुरक्षा योजना में हमारी सरकार ने 85 लाख नाम जोड़कर पात्र लोगों को राहत दी है। 24 जिलों के किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति की जा रही है, जो कि वर्ष 2027 तक प्रदेश भर में उपलब्ध होगी।

लखीमपुर खीरी में वैन और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने शोक जताया

लखीमपुर खीरी (उप्र)/भाषा। लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा क्षेत्र के ईसानगर थाना इलाके में सोमवार सुबह एक मैजिक वैन और ट्रक की टक्कर में चालक और दो महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजन तथा घायलों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। धौरहरा के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि हादसा सिसैया-लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-730 पर ईसानगर और धौरहरा कोतवाली क्षेत्र की सीमा पर उंचगांव और भरेहता गांव के बीच हुआ। उन्होंने बताया कि यह वैन लखीमपुर से बहराइच की ओर जा रही थी और इसमें चालक के अलावा नौ यात्री सवार थे। सिंह ने बताया कि मैजिक वैन और ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई, जिसमें वैन में सवार सभी लोगों की जान चली गई।

झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मानव संसाधन को मजबूत कर रही है सरकार : हेमंत सोरेन

रांची/भाषा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए विभिन्न विभागों में मानव संसाधन को मजबूत कर रही है। सोरेन ने यह बात प्रोजेक्ट भवन में 316 नवनियुक्त शिक्षकों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास में तेजी लाने के लिए विभिन्न विभागों में मानव संसाधन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। आपके (नवनियुक्त कर्मियों) माध्यम से हम गांवों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं से जुड़ेंगे और उन्हें भविष्य के लिए और मजबूत बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सामाजिक और भौगोलिक रूप से अन्य राज्यों से अलग है, और यहां के लोगों ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर, विशेषकर खेल और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय का जिक्र करते हुए सोरेन ने कहा कि इस संस्थान ने देश को बड़ी संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारी दिए हैं। उन्होंने कहा, कुछ ऐसे काम जो राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में ही हो जाने चाहिए थे, वे विभिन्न कारणों से नहीं हो सके।

ओडिशा में प्रधानाध्यापक रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया

केंद्रपाड़ा (ओडिशा)/भाषा। ओडिशा सतर्कता विभाग ने सोमवार को केंद्रपाड़ा जिले में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक कर्मचारी से कथित तौर पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान रघुनाथ दास के रूप में हुई है और वह महाकालपाड़ा के पास चादेइगुआन स्थित एक हाई स्कूल में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत था। अधिकारियों के अनुसार, शिकायतकर्ता हाल ही में नियुक्त कर्मचारी है और उसे अगस्त 2025 में स्कूल में नौकरी की शुरुआत करने के बाद से वेतन नहीं मिला था। कर्मचारी ने कथित तौर पर कई बार प्रधानाध्यापक से संपर्क कर अनुरोध किया था कि वह लंबित वेतन राशि के भुगतान के लिए उपस्थिति पत्रक को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), केंद्रपाड़ा के कार्यालय में अधिकारी को उपलब्ध करा दें। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कथित तौर पर 5,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद सतर्कता अधिकारियों ने जाल बिछा दास को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार की जांच के लिए दो समितियां बनाने को दी मंजूरी : शुभेंदु

कोलकाता/भाषा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में दो अलग-अलग समितियों के गठन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि दोनों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने अपनी सहमति दे दी है और समिति एक जून से काम करना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये फैसले चुनाव प्रचार के दौरान किये गए वादे से जुड़े हैं और जनहित में किये गए हैं। उन्होंने बताया कि संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाली समिति की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु करेंगे, वहीं भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एडीजी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी जयरमन इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

पार्क सर्कस में हिंसा पर बोले शुभेंदु अधिकारी

पुलिसकर्मियों पर हमलों को कतई सहन नहीं किया जायेगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि ऐसी घटनाएं दोबारा हुईं, तो ''मुझसे बुरा कोई नहीं होगा''।

कोलकाता के तिलजला में हाल में हुई 'बुलडोजर कार्रवाई' के खिलाफ प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गया था। पार्क सर्कस क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर पथराव किया था, जिसमें कुछ अधिकारी घायल हो गये थे और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा था। पार्क सर्कस के उपायुक्त कार्यालय का दौरा करने और पुलिस अधिकारियों और घायल कर्मियों से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कानून-व्यवस्था की स्थिति के प्रति कड़ा रुख अपनाया। शुभेंदु ने बताया कि हिंसा में छह पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच की निगरानी सीधे पुलिस आयुक्त द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा, ''मैं स्पष्ट संदेश दे रहा हूं कि इस तरह की अशांति, गुंडागर्दी और राष्ट्रविरोधी, समाजविरोधी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। हम ऐसी चीजों को जारी नहीं रहने देंगे।''

शुभेंदु अधिकारी ने घायल कर्मियों से मुलाकात की और मीडिया के सामने उनके नाम पढ़े। उन्होंने पुलिस और केंद्रीय बलों के आचरण की प्रशंसा की और कहा कि भीड़ द्वारा उकसाये जाने के बावजूद उन्होंने संयम बरता। उन्होंने कहा कि मैं घायल पुलिसकर्मियों व सीआरपीएफ जवानों का हालचाल जानने के लिए आया हूं।

सीजेआई ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से डिजिटल माध्यम से सुनवाई का आग्रह किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर अनावश्यक खर्च में कटौती करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से फिलहाल सोमवार और शुक्रवार को 'डिजिटल' माध्यम से सुनवाई करने का आग्रह किया है।

शीर्ष अदालत ने 15 मई को, सोमवार और शुक्रवार को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया। न्यायाधीशों ने ईंधन के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक-दूसरे के वाहन से न्यायालय आने-जाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का ''सर्वसम्मति से संकल्प'' लिया। पश्चिम एशिया संकट के कारण अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के बाद यह कदम उठाया गया। सोमवार को, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी का एकीकरण हुआ है और ऑनलाइन सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने ''अतिरिक्त धैर्य'' दिखाया। रोहतगी ने कहा, ''मैं ऑनलाइन सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना करता हूं, क्योंकि आज सभी अदालतों में यह सुचारू रूप से संपन्न हुई।''

प. बंगाल में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक बढ़ाई

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को पांच वर्ष तक बढ़ाने की सोमवार को घोषणा की। मुख्य सचिव के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ए, बी, सी, और डी समूह की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए संशोधित आयु सीमा वित्त विभाग की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद 11 मई से प्रभावी हो गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है, सरकार के संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (डब्ल्यूबीपीएससी) के जरिए भर्ती के लिए संशोधित नियमों के तहत ग्रुप 'ए' पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 41 वर्ष, ग्रुप 'बी' पदों के लिए 44 वर्ष और ग्रुप 'सी' तथा ग्रुप 'डी' पदों के लिए 45 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन पदों के लिए पहले से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा इससे अधिक है, वहां मौजूदा सीमा ही लागू रहेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के अलावा अन्य माध्यमों से होने वाली नियुक्तियों जैसे वैधानिक निकायों, सरकारी कंपनियों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है। विज्ञप्ति के अनुसार संशोधित नियमों के तहत पहली भर्ती प्रक्रिया कॉलेज सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पदों के लिए होगी, जिसकी चयन प्रक्रिया जारी है।

आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह 'आर्ट ऑफ़ गिविंग' की वजह से हूँ : डॉ अच्युत सामंत

आर्ट ऑफ़ गिविंग दिवस पर समाजसेवियों को दिया 'एओजी हीरो अवॉर्ड्स'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फारमेशन टेक्नालॉजी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस व आर्ट ऑफ गिविंग (एओजी) के संस्थापक डॉ अच्युत सामंत द्वारा स्थापित 'आर्ट ऑफ गिविंग(एओजी) अर्थात दान देने की कला' सामाजिक पहल का 13वां इंटरनेशनल आर्ट ऑफ़ गिविंग डे इस वर्ष छह महाद्वीपों के 190 देशों में मनाया गया। इसके अलावा, आर्ट ऑफ़ गिविंग मूवमेंट के प्रशंसकों और शुभचिंतकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 हजार स्थानों पर इस अभियान में हिस्सा लिया। अकेले ओडिशा में यह दिन 20 हजार स्थानों पर मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी 'शेयर टू शाइन', जिसका मतलब है कि दूसरों के साथ खुशियाँ बाँटने से खुद की भी तरक्की होती है। इस वर्ष के महोत्सव के हिस्से के तौर पर ओडिशा में 3 हजार से ज़्यादा जगहों पर वॉलीबॉल और नेट बांटने का इंतज़ाम किया गया था।

अच्युत सामंत द्वारा खेल विकास और युवाओं के बीच मेलजोल और दोस्ती को बढ़ावा देने के विज़न से प्रेरित होकर इस वर्ष 9,100 वॉलीबॉल बांटी गई। डॉ. सामंत ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह आर्ट ऑफ़ गिविंग' पहल के वजह से हूँ। इस अभियान की वजह से मुझे लोगों का प्यार और अपनापन मिला है। भुवनेश्वर में आयोजित इस कार्यक्रम में मशहूर हिंदी पार्श्व गायक शान का गाया हुआ आर्ट ऑफ़ गिविंग थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा सदस्य रवींद्र नारायण बेहरा, भारतीय टेनिस लेजेंड और पद्म भूषण विजेता लिएंडर पेस, तिब्बती बौद्ध गुरु और स्विट्जरलैंड के रिपा इंटरनेशनल सेंटर के स्पिरिचुअल डायरेक्टर गेट्रुल जिग्मे रिनपोछे और फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल शामिल हुए। इस वर्ष भी समाजसेवा में विशेष कार्य करने वाले जाने-माने मेडिकल एक्सपर्ट डॉ. विद्युत दास, रोटेरियन अजय अग्रवाल और केआईआईटी के प्रोफेसर कुमार देबदत्त को 'एओजी हीरो अवॉर्ड्स' के रूप में एक लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर केआईआईटी व केआईआईएस के कुलपति प्रोफेसर सरनजीत सिंह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए।

आरटीआई अधिनियम के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है बीसीसीआई : सीआईसी

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सोमवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए वह पारदर्शिता कानून के तहत किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके साथ ही सीआईसी ने इस संबंध में 2018 का अपना ही आदेश पलट दिया।

सूचना आयुक्त पी. आर. रमेश ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), यद्यपि क्रिकेट प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के प्रतिनिधित्व से जुड़े महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य करता है, फिर भी उसे 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह न तो सरकार के स्वामित्व में है, न सरकार द्वारा नियंत्रित है और न ही सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित है।

सूचना आयुक्त रमेश ने अपने आदेश में कहा, ''बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम की धारा 2(एच) के अर्थ में 'सार्वजनिक प्राधिकरण' के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए वर्तमान मामले की परिस्थितियों में आरटीआई अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते हैं।''

पिछली सरकारों की सोच 'कट्टा' और बम तक ही सीमित थी : आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज करते हुए सोमवार को कहा कि पहले राज्य में बम और 'कट्टा' बनाए जाते थे लेकिन अब इस सूबे में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों की सोच बम और 'कट्टा' (देसी पिस्टल) तक ही सीमित थी।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में एक प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा, पिछली सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में आखिर होता क्या था? उनका उत्पादन क्या था? वह 'कट्टा' और बम थे, जिनका निर्माण यहां होता था, है ना? आज, हमने उन कट्टा और बमों के उत्पादन पर रोक लगा दी है। अब यहां ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में राष्ट्र की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन किया जा रहा है। कई तरह के ड्रोन, चाहे वे खेतों में रसायन और उर्वरक छिड़कने के लिए इस्तेमाल होने वाले 'ड्रोन दीदी' के ड्रोन हों, या किसी दुश्मन या पाकिस्तान के हवाई अड्डों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किए ड्रोन हों, सभी का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आदित्यनाथ ने दावा किया, चूंकि पिछली सरकारों की सोच 'कट्टा' और बम तक ही सीमित थी इसीलिए वे बम फेंकने में ही लगे रहते थे। हर एक क्षेत्र में गिरावट की स्थिति बनी हुई थी। उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा, आज हालात अलग हैं। रक्षा उत्पादन गलियारे ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, और अब यह राज्य रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

इंडियन स्कीमर 20 साल बाद भागलपुर के विक्रमशिला डॉल्फिन रिजर्व में लौटा : नमामि गंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। विलुप्तप्राय नदी-जल पक्षी इंडियन स्कीमर, लगभग 20 वर्षों के बाद बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला डॉल्फिन रिजर्व में लौट आया है। जल शक्ति मंत्रालय ने इस घटनाक्रम को गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार का प्रमाण बताया है।

इंडियन स्कीमर को लंबे समय से एक संकेतक प्रजाति माना जाता रहा है क्योंकि इसकी निर्भरता साफ मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और मछली की पर्याप्त उपलब्धता पर है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल नमामि गंगे पर पोस्ट में कहा कि यह वहीं रहता है जहां पानी साफ हो और मछलियां भरपूर हो। पोस्ट में कहा गया है, ''यह कोई आम पक्षी नहीं है। यह वहीं रहता है जहां पानी साफ हो, बहाव सही हो और मछलियां भरपूर हो। जहां नदी बीमार है, यह वहां नहीं ठहरता।'' पक्षी के महत्व को रेखांकित करते हुए पोस्ट में कहा गया, ''बीस साल। दो दशक। एक पूरी पीढ़ी।'' इसमें कहा गया है, ''जैव विविधता वापस आ रही है। नदी का पारिस्थितिकी तंत्र फिर से संतुलन की ओर है।'' पोस्ट में कहा गया है कि विक्रमशिला डॉल्फिन रिजर्व में स्कीमर का लौटना सिर्फ एक संकेत नहीं, एक प्रमाण है कि पानी की गुणवत्ता सुधर रही है। इसमें कहा गया है, ''गंगा सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है। यह डॉल्फिन, मछली, पक्षी और नदी किनारे बसे करोड़ों लोगों का साझा घर है। जब नदी ठीक होती है, तो जीवन अपने आप लौट आता है। यह तो बस शुरुआत है।''

उप्र पुलिस ने नौ वर्ष में 289 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया; 34,253 गिरफ्तार

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त न करने (जीरो टॉलरेंस) की नीति के तहत सतत कार्रवाई करते हुए पिछले नौ वर्षों में 289 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, इस अवधि में पुलिस के साथ मुठभेड़ की कुल 17,043 घटनाएं हुईं, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें बताया गया है कि इन मुठभेड़ में कुल 11,834 अपराधी घायल हुए। इस दौरान अपराधियों से मोर्चा लेते वक्त 18 पुलिसकर्मी शहीद और 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए। बयान में कहा गया है कि मुठभेड़ की सबसे अधिक 4,813 घटनाएं मेरठ ज़ोन में हुईं। इस कार्रवाई में 8,921 अपराधी दबोचे गये और 3,513 अपराधी घायल हुए, जबकि 97 कुख्यात अपराधी मौके पर ही मारे गये। बयान के अनुसार, मेरठ जोन में हुई मुठभेड़ के दौरान 477 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दो पुलिसकर्मी शहीद हो गये।

एशियाई खेलों के ट्रायल के लिये विनेश को राहत नहीं, दूसरा पक्ष सुनकर ही फैसला देगी अदालत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पहलवान विनेश फोगाट को 'दूसरे पक्ष की बात सुने बिना' तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। विनेश ने अदालत से 30 और 31 मई को एशियाई खेलों के लिये होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

भारतीय कुश्ती महासंघ ने उन्हें ट्रायल में भाग लेने से अयोग्य करार दिया है। अदालत ने विनेश को डब्ल्यूएफआई के कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब देने के लिये कहा है। महासंघ ने उस पर अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने महासंघ को निर्देश दिया कि कारण बताओ नोटिस को छह जुलाई तक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाये और उनके समक्ष फैसला रखें।

अदालत ने 'अयोग्यता' को लेकर विनेश की याचिका पर डब्ल्यूएफआई और केंद्र को नोटिस दिये हैं और कहा कि इस मामले में 'प्रतिस्पर्धी हितों' के बीच संतुलन बनाये रखना जरूरी है।

विनेश की ओर से सीनियर अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें 30 और 31 मई को होने वाले एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने दिया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व अवकाश पर गई महिला एथलीटों की रैंकिंग और दर्जे को सुरक्षित रखा जाता है, वहीं डब्ल्यूएफआई की नवीनतम नीति ने उन्हें इससे बाहर रखा है। न्यायमूर्ति कौरव ने कहा, '' आपको पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हम दूसरे पक्ष को सुने बिना आपको वह राहत कैसे दे सकते हैं। डब्ल्यूएफआई की नीति को देखना होगा। इसमें आपसी हित जुड़े हुए हैं। हाँ, हम मानते हैं (कि आप मातृत्व अवकाश पर थीं), लेकिन साथ ही, देश का हित भी देखना है।'' उन्होंने मौखिक रूप से कहा, ''इसलिए, उन्हें जवाब फाइल करने दें।

अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय दिया है।

सरकार का लक्ष्य लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बनाना : सम्राट

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार से बाहर रह रहे लोगों से राज्य में लौटकर उद्योग स्थापित करने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश को समृद्ध बनाने में सभी की भूमिका होनी चाहिए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और सरकार का लक्ष्य लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति बड़े पैमाने पर निवेश के लिए बिहार आ रहे हैं और सरकार का लक्ष्य 20 नवंबर 2026 तक राज्य में पांच लाख करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित करना है। सम्राट ने यह बात 80 अत्याधुनिक दमकल वाहनों को हरी झंडी दिखाने और एआई आधारित आधुनिक दमकल नियंत्रण कक्ष के उद्घाटन के मौके पर कही। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है तथा गया में भी ऐसा केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के अधिक उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे परियोजनाओं की लागत में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस को पूरी छूट दी गई है और बिहार को सुशासन वाला राज्य बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।

सुविचार

सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

जन्म दर के लिए लोकलुभावन प्रयोग!

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि (क्रमश: 30,000 रुपए और 40,000 रुपए) दिए जाने के संबंध में जो घोषणा की है, उससे एक नई बहस शुरू हो गई है। इस घोषणा से कई सवाल भी पैदा होते हैं। अब तक यह पढ़ने-सुनने को मिलता था कि 'भारत में जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए किसी तरह इस पर काबू पाएं।' वहीं, आंध्र प्रदेश में अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। यहां सरकार संतान पैदा करने पर रुपए देगी! पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि क्या आंध्र प्रदेश में सच में ऐसी स्थिति आ गई है, जिसके कारण सरकार को आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणा करनी पड़ी? जापान, सिंगापुर, स्वीडन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में जन्म दर में भारी गिरावट आने के कारण उनकी सरकारें आर्थिक सहायता कार्यक्रम चला रही हैं, लेकिन ये बहुत समृद्ध देश हैं। वहां नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि के लिए गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारत में इन सुविधाओं पर पहले ही काफी दबाव है। ऐसे में और ज्यादा संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहन देने का क्या औचित्य है? क्या जो बच्चे जन्म लेंगे, उनके लिए अच्छे सरकारी स्कूल हैं? क्या सरकारी अस्पताल वर्तमान जनसंख्या को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रहे हैं? क्या सार्वजनिक परिवहन सेवाएं इतनी बेहतर हो गई हैं कि वे और ज्यादा जनसंख्या का बोझ बर्दाश्त कर सकें? क्या रोजगार देने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना है? क्या उन बच्चों के लिए साफ पानी, साफ हवा और शुद्ध भोजन है? अगर कोई राज्य सरकार अपने यहां घटती जन्म दर को लेकर सच में चिंतित है तो पहले इन सवालों पर ध्यान दे।

जो लोग इस धरती पर आ चुके हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। महंगाई ने कई परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे माहौल में कोई दंपति दो बच्चे पाल ले, वही आज बहुत बड़ी बात है। अब कई शहरों में डिंक (डबल इनकम, नो किड्स) का चलन बढ़ता जा रहा है। उन दंपतियों ने यह फैसला रातोंरात नहीं लिया है। राज्य सरकारें अच्छे स्कूल, अस्पताल, आवास और रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं दे पाईं, इसलिए वे उनके भरोसे किसी बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहते। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। सिर्फ कुछ हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि घोषित कर देने मात्र से कितने लोग इसे गंभीरता से लेंगे? इतनी राशि से तो एक अच्छे स्कूल में पहली कक्षा की फीस नहीं भरी जा सकती। उस बच्चे को पाल-पोसकर बड़ा करने, उसे किसी रोजगार लायक बनाने में बहुत रुपए खर्च होंगे। सरकारें सबसे पहले शिक्षा की ओर ध्यान दें। सरकारी स्कूलों की हालत सुधार दें। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में जनसंख्या के अनुपात में सुविधाएं बढ़ा दें। ये दो काम पूरी ईमानदारी से हो जाएं तो लोगों के सिर से भारी बोझ हट जाए। इसके बाद स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव करना होगा। बच्चों को वह सिखाएं, जो उनके जीवन में काम आए। पांचवीं कक्षा के बाद रोजगार संबंधी जानकारी देना शुरू कर दें। दसवीं कक्षा पास करते-करते हर बच्चे में कामकाज संबंधी समझ पैदा हो जाए। जब वह कॉलेज में पहुंचे तो उसके पास कम-से-कम तीन ऐसे हुनर हों, जिनके जरिए वह अपनी रोटी खुद कमा सके। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से कहीं ज्यादा आसान होना चाहिए- स्वरोजगार शुरू करना और उसे आगे बढ़ाना। सरकारें बुनियादी ढांचे को इतना मजबूत बना दें कि किसी को पढ़ाई, दवाई और कमाई की चिंता ही न करनी पड़े। इससे जन्म दर को संतुलित और स्थिर रखने में मदद मिलेगी। संतानोत्पत्ति के मामले में शिक्षित वर्ग लोकलुभावन प्रयोगों पर विश्वास नहीं करेगा।

ट्वीटर टॉक

जब भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो पूरी दुनिया ने भारत की ताकत, पक्के इरादे और हमारी साइंटिफिक काबिलियत का लोहा माना। यह ऐतिहासिक कामयाबी हमारी साइंटिफिक टैलेंट के साथ-साथ उस समय की इंदिरा गांधी की दूर की सोचने वाली और कुशल लीडरशिप का सबूत थी।

-अशोक गहलोत

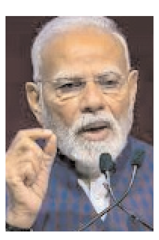

ओस्लो में वेलकम प्रोग्राम के दौरान नाटियालया डांस स्कूल के एक ग्रुप ने अलारिप्पु परफॉर्म किया, जो भरतनाट्यम से जुड़ा है। यह टीम लगभग तीन दशकों से नॉर्वे में भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पॉपुलर बना रही है। ऐसी कोशिशें वाकई तारीफ के काबिल हैं।

-नरेन्द्र मोदी

भारत में एडवेंचर टूरिज्म अब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं रहा इस पर आज दिल्ली में इंडियन एडवेंचर टूरिज्म-रिस्क मैनेजमेंट सेमिनार में जाने-माने पत्रकार राहुल कंवल और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के प्रेसिडेंट अजीत बजाज के साथ चर्चा हुई।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत

प्रेरक प्रसंग

मृत्यु-भय

सम्राट अशोक के छोटे भाई वीतशोक को श्रमण-भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उन्हें लगता ये सब उत्तम भोजन-वस्त्र के लोभ से भिक्षु बने हैं। उन्हें समझाने के लिए अशोक ने एक युक्ति सोची। एक दिन मंत्रियों ने वीतशोक से कहा सम्राट के बाद आप ही राजा होंगे। जरा ये वस्त्राभूषण पहनकर दिखाइये तो, आप कैसे लगते हैं। वीतशोक राजसी वस्त्र-अलंकार धारण कर सिंहासन पर बैठे ही थे कि सम्राट आ गये। उन्होंने कहा, 'मेरे रहते तुम्हारा यह दुस्साहस! तुम्हें राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दिया जायेगा।' मंत्रियों के अनुनय-विनय करने पर अशोक ने कहा, 'ठीक है। प्राणदंड तो अवश्य मिलेगा किन्तु यह मेरा प्रिय भाई है, पहले एक सप्ताह तक राजसुख भोगे।' वीतशोक सात दिन के लिए राजा हुए। राजसी ऐश्वर्य से परिपूर्ण सात दिन। किन्तु उसके पीछे हर समय दो खड्गधारी वधिक चलते जो उन्हें प्रतिक्षण आसन्न-मृत्यु की याद दिलाते रहते। सात दिन बाद वीतशोक को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्राट ने हंसकर पूछा, 'कहो बंधु, कैसा लगा राजपद का सुख?' वीतशोक ने कहा' 'कैसा सुख? कहां का भोग-विलास? जिसके पीछे हर समय नंगी तलवारें लिये मृत्यु चल रही हो, उसके लिये ये सुख भला किस काम के?'

सामयिक

चीन-अमेरिका की निकटता से भारत के सामने वैश्विक चुनौतियां

ललित गर्ग
मो. 9811051133

दुनिया एक बार फिर ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहाँ दो महाशक्तियों-अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते संवाद, आपसी मुलाकातों और कूटनीतिक समीकरणों को केवल द्विपक्षीय संबंधों के रूप में नहीं देखा जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संवाद और संभावित समझौतों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाओं का दौर चल रहा है। एक वर्ग इसे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए राहतकारी कदम मान रहा है, क्योंकि इससे बढ़ती महंगाई, व्यापारिक अवरोधों और युद्धजन्य संकटों में कमी आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि यह निकटता भविष्य में एक ऐसे विश्व संरचना को जन्म दे सकती है जहाँ दुनिया की दिशा पुनः कुछ महाशक्तियों के हाथों में सिमट जाए और विकासशील तथा अर्धविकसित देशों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी हो जाएँ। भारत जैसे देशों के लिए यह परिस्थिति अवसर और चुनौती दोनों लेकर आई है। आज अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 44 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करते हैं। विश्व व्यापार, तकनीकी विकास, ऊर्जा बाजार, वैश्विक निवेश, वित्तीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक निर्णयों पर इन दोनों देशों का गहरा प्रभाव है। ऐसे में इनके संबंधों में किसी भी प्रकार का बदलाव पूरी दुनिया की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, टैरिफ विवाद, तकनीकी प्रतिबंध और ताइवान से जुड़े तनावों ने विश्व अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाला। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ टूट गईं, रूस-यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा संकट बढ़ाया और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेला। इन परिस्थितियों में यदि अमेरिका और चीन संवाद और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बल मिल सकता है।

विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने से सबसे पहले वैश्विक बाजारों को राहत मिलेगी। निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, तकनीक तथा विनिर्माण क्षेत्रों में लागत घट सकती है। इससे महंगाई पर भी नियंत्रण संभव है। किंतु यह केवल तस्वीर का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि यदि दोनों महाशक्तियाँ वैश्विक व्यापारिक नियमों और आर्थिक नीतियों को अपने हितों के अनुसार तय करने लगें तो छोटे देशों की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। दुनिया पहले भी उपनिवेशवाद और आर्थिक नियंत्रण की राजनीति देख चुकी है, अब आशंका यह है कि कहीं आर्थिक वैश्वीकरण का नया स्वरूप महाशक्तियों के संयुक्त वर्चस्व में परिवर्तित न हो जाए। इसी संदर्भ में जी-2 यानी अमेरिका और चीन केंद्रित विश्व व्यवस्था की चर्चा तेज हुई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विश्व धीरे-धीरे बहुध्रुवीय व्यवस्था से हटकर दो महाशक्तियों के प्रभाव वाले ढाँचे की ओर बढ़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक नीतियों, व्यापारिक समझौतों और सुरक्षा संबंधी निर्णयों में छोटे देशों की भूमिका सीमित हो सकती है। यह स्थिति भारत जैसे देशों के लिए विशेष चिंता का विषय है क्योंकि भारत हमेशा से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और सामूहिक वैश्विक नेतृत्व का समर्थक रहा है।

भारत की स्थिति यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत न तो पूरी तरह अमेरिकी खेमे में है और न ही चीन के प्रभाव क्षेत्र में। भारत ने लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाई है। अमेरिका के साथ भारत के रक्षा, तकनीकी और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। क्वाड जैसे मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका है। दूसरी ओर चीन भारत का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच सीमा विवादों के बावजूद व्यापारिक संबंध व्यापक हैं। यही कारण है कि अमेरिका और चीन की बढ़ती निकटता भारत के लिए केवल बाहरी घटना नहीं बल्कि रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन का विषय है।

भारत और चीन की तुलना करें तो चीन ने पिछले तीन दशकों में विनिर्माण, निर्यात, आधारभूत संरचना और तकनीकी उत्पादन के माध्यम से स्वयं को वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित किया। चीन की आर्थिक नीति केंद्रीकृत और तीव्र निर्णय क्षमता वाली रही है। इसके विपरीत भारत का विकास लोकतांत्रिक व्यवस्था, विविधता और संस्थागत संतुलन पर आधारित रहा है। भारत की शक्ति उसकी युवा आबादी, लोकतंत्र, सेवा क्षेत्र और डिजिटल क्षमता में निहित है, जबकि चीन की शक्ति विनिर्माण, निर्यात और पूंजी निवेश में रही है। अमेरिका के साथ चीन के संबंधों में सुधार होने की स्थिति में भारत के सामने यह चुनौती होगी कि वह अपनी आर्थिक और रणनीतिक उपयोगिता को और अधिक प्रभावशाली बनाए।

भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर चाइना प्लस वन रणनीति में निहित है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पिछले वर्षों में चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयास किए हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ चीन के विकल्प के रूप में भारत, वियतनाम और अन्य देशों की ओर बढ़ी हैं।

भारत यदि अपनी औद्योगिक नीतियों, आधारभूत संरचना, श्रम सुधार और तकनीकी क्षमता को मजबूत करता है तो वह वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बन सकता है। किंतु यदि भारत आवश्यक गति से सुधार नहीं कर पाया तो यह अवसर अन्य देशों के पास चला जाएगा। तकनीकी क्षेत्र में भी अमेरिका-चीन संबंधों का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और रेयर अर्थ मिनरल्स नई शक्ति राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। अमेरिका तकनीकी श्रेष्ठता बनाए रखना चाहता है जबकि चीन तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत इन दोनों के बीच एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर सकता है, लेकिन इसके लिए अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। भारत के पास प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा को वैश्विक नेतृत्व में बदलने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि चाहिए।

भू-राजनीतिक दृष्टि से भी यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संकटों पर अमेरिका और चीन की भूमिका निर्णायक है। यदि दोनों देशों के बीच समझ बढ़ती है तो सैन्य टकरावों की आशंका कम हो सकती है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर होंगे और तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश के लिए यह अत्यंत लाभकारी स्थिति होगी। लेकिन यदि दोनों महाशक्तियाँ अपने प्रभाव विस्तार के लिए संकटों का उपयोग करती हैं तो विश्व अस्थिरता और बढ़ सकती है। भारत की विदेश नीति के लिए यह समय अत्यंत निर्णायक है। भारत को अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हुए चीन के साथ व्यावहारिक संबंधों का संतुलन बनाना होगा। साथ ही उसे वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका और मजबूत करनी होगी। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने जिस वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की अवधारणा प्रस्तुत की थी, वह भविष्य की विश्व व्यवस्था का वैकल्पिक मॉडल बन सकती है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अमेरिका और चीन जहाँ शक्ति संतुलन की राजनीति में उलझे हुए हैं, वहीं भारत सहअस्तित्व, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग की नीति पर चल रहा है। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा शक्ति प्रदर्शन पर आधारित है जबकि भारत का दृष्टिकोण विकास, मानवीय मूल्यों और वैश्विक साझेदारी पर केंद्रित रहा है। यही भारत की विशिष्टता और शक्ति है।

आज दुनिया में यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि क्या अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया को पुनः अपने प्रभाव क्षेत्र में बाँटने का प्रयास करेंगे? क्या छोटे देशों की भूमिका सीमित हो जाएगी? क्या फिर वही स्थिति बनेगी जब महाशक्तियाँ विश्व राजनीति को अपनी उँगलियों पर नचाती थीं?

इन प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि आज की दुनिया शीत युद्ध काल की दुनिया नहीं है। भारत, जापान, यूरोपीय संघ, ब्राजील, आसियान और अफ्रीकी देशों का बढ़ता प्रभाव विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवीय बनाए रखने में सक्षम है। भारत को इस बदलती परिस्थिति में अपने संकल्पों को सुदृढ़ करना होगा, विकास के नए मानक गढ़ने होंगे और अपनी रणनीतिक क्षमता को विस्तार देना होगा। क्योंकि बदलती दुनिया में प्रश्न यह नहीं है कि अमेरिका और चीन क्या करेंगे, बल्कि यह है कि भारत स्वयं को किस ऊँचाई पर स्थापित करेगा।

नजरिया

दहेज के कारण आखिर कब तक जान गंवाती रहेंगी महिलाएं ?

अशोक भाटिया
मोबाइल : 9221232130

दहेज लेना एक रूढ़ीवादी सांस्कृतिक परंपरा है जो पितृसत्ता को पोषित करती है। संस्कृति के रूप में इसे चलाए रखा जाता है और आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित किया जाता है,जिससे पितृसत्ता का वजूद बना रहे और पुरुष स्त्री को संपत्ति की तरह हासिल कर उसका स्वामी बन सके। दहेज प्रथा के कारण महिलाएं समाज में दोयम दर्जे की मानी जाती हैं। जन्म से ही उन्हें 'पराया धन' कहकर परिवार के सभी संसाधनों से अलग-थलग कर दिया जाता है।

नोएडा की 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा, जो पूर्व मिस पुणे भी रह चुकी थीं, मात्र पांच महीने की शादी के बाद भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में 12 मई 2026 की रात संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी मिलीं। शादी दिसंबर 2025 में डेटिंग ऐप पर मिले वकील समर्थ सिंह के साथ हुई थी। ट्विशा हाल ही में दो महीने की प्रेग्नेंट थीं, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में एक हफ्ते पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (चढ्ढज) का खुलासा हुआ। मायके पक्ष का दावा है कि यह जबरन अबॉर्शन था, जिसमें सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह ने मानसिक यातना देकर ट्विशा को मजबूर किया। परिवार ने आरोप लगाया कि ट्विशा को पितृत्व पर संदेह कर उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए, जिससे उस पर जबरदस्त मेंटल टॉर्चर हुआ। इस मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मल्टीपल एंटीमॉर्टम इंजरी (मौत से पहले की कई चोटें) मिलने से हत्या की आशंका और मजबूत हो गई है। मामला इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और उनके माता-पिता रिटायर्ड जज रह चुके हैं। ट्विशा के परिवार ने इसे आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या करार दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जबरन गर्भपात, शरीर पर चोटों के निशान और मौत से पहले की आखिरी कॉल जैसे कई तथ्य अब इस मामले को और रहस्यमयी बना रहे हैं।

चूंकि आरोपी परिवार न्यायिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है, इसलिए ट्विशा के परिजनों ने स्थानीय पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि प्रभाव के चलते पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। इसी वजह से परिवार ने मध्य प्रदेश से बाहर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं, सास को अग्रिम जमानत मिलने के बाद परिवार ने शव लेने से इनकार करते हुए दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई है। वैसे गिरिबाला सिंह के खिलाफ शुक्रवार को भोपाल पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है । इसके बाद गिरिबाला सिंह ने भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी। शुक्रवार देर शाम तक चली सुनवई और परिजनों के विरोध के बावजूद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई। सिंह को अग्रिम जमानत मिलने के बाद से परिजन और आक्रोशित हो गए और कहने लगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी चीजों का उल्लेख नहीं है, इसलिए लिए अग्रिम जमानत मिल गई है। सोमवार 18 मई को ट्विशा के पति और अधिवक्ता समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत पर भोपाल जिला न्यायालय में सुनवाई होनी है। अग्रिम जमानत मिलने के बाद से ही परिजन अधिक आक्रोशित हैं। खैर अब यह न्यायिक प्रतिक्रिया में उलझा मामला चलता रहेगा व इसके रिजल्ट की हमें प्रतिक्षा ही करनी होगी ।

वैसे ट्विशा शर्मा की दहेज़ हत्या का सामने आया पहला मामला नहीं है । इसके पहले भी केरल के कोल्लम ज़िले में बीते 21 मार्च को एक 27 साल की महिला थूशरा की मौत हो गई। मौत के वक्त उसका वज़न महज़ बीस किलो रह गया था। दरअसल, थूशरा की शादी के वक्त दो लाख रुपए दहेज की मांग रखी गई थी जो उसके माता-पिता नहीं दे पाए। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसका पति और सास उसका शोषण करते थे। उन्होंने स्वीकार भी किया कि थूशरा को खाने के लिए रोज़ पानी मिलाकर चावल और चीनी के अलावा कुछ और नहीं दिया जाता था। वहां के पोस्टमैन ने पुलिस को बताया कि इस घटना की जानकारी पड़ोसियों को न हो, इसके लिए थूशरा को टिन की घेराबंदी वाले घर के भीतर कैद कर के रखा गया था। यह घटना भारत के सर्वाधिक शिक्षित राज्य की है। यह घटना आज की है। यह घटना दहेज हत्या की श्रेणी में ही आएगी। वह दहेज हत्या जो उत्तर-आधुनिक समय में भी न जाने कितनी महिलाओं की मौत का कारण बनती है।

गौरतलब है कि शादी-शुदा महिलाओं की हत्याएं, जिन्हें ससुराल में पति और अन्य सदस्यों ने दहेज के लिए या तो क़त्ल कर दिया गया हो अथवा लगातार उत्पीड़न और यातना देकर आत्महत्या के लिए बाध्य किया जाए, दहेज हत्या कहलाती है। दहेज हत्या एक ऐसा अपराध है जहां महिलाओं के लिए उनके अपने घर ही सबसे असुरक्षित स्थान बन जाते हैं। दहेज और उससे जुड़े अपराधों के मामले में भारत दुनियाभर में पहले स्थान पर आता है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान आते हैं, जहां दहेज हत्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है।

दहेज हत्या मूल रूप से पितृसत्ता का ही एक रूप है जिसकी जड़ें प्राचीन इतिहास के कबीलाई परंपराओं में छिपी हैं। लिंग आधारित श्रम विभाजन के बाद कबीलों में एक संस्कृति विकसित हुई जिसके तहत महिलाओं का आदान-प्रदान होता था। कबीले के अस्तित्व के लिए महिलाएं चुप रहती थी जो बाद में संस्कृति के रूप में उनके शोषण का आधार बनी। इस प्रक्रिया में महिलाओं के साथ-साथ पशुओं, कीमती पत्थरों और ज़रूरी सामानों का भी आदान-प्रदान होता था जिससे बेहतर संबंध स्थापित हो। बाद में इस प्रक्रिया के तहत महिलाएं पुरुषों की संपत्ति मानी जाने लगी और उनका अपने पर कोई अधिकार नहीं रहा। आज के उत्तर-आधुनिक समाज में भी स्त्री दर्जे में पुरुष से कमतर मानी जाती हैं, इसलिए उसकी स्वीकारोक्ति के लिए शादी में धन की कई बार खुली और कभी मूक मांग रखी जाती है। इस मांग को यह कहकर जायज़ ठहराया जाता है कि लड़की के माता-पिता जो कुछ भी दे रहे हैं, उनकी बेटी के लिए ही हैं। यह एक तरह से सौदा होता है, जिसमें किसी लड़की को ब्याहने के लिए लड़का और उसके परिवार वाले मोटी रक़म चाहते हैं। दहेज की मांग भारतीय समाज में सामान्य बात हो चुकी है।

दहेज की प्रथा मानो शादी का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। यह प्रथा सभी समूहों में मौजूद है चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के हों। लड़की ब्याहने के लिए लड़के के परिवार की हैसियत के अनुसार दहेज देना पड़ता है। यह ब्याह होने की अनिवार्य शर्त भी है। रूढ़िवादी भारतीय समाज शादी की संस्था और पारिवारिक संरचना में सुधार करने की बजाय इसे पारंपरिक रूप में ही चलाना चाहता है। इस समाज के लिए यह महत्वपूर्ण है ही नहीं कि शादी से पहले लड़के और लड़की में सामंजस्य और आपसी समझ विकसित हो, जिससे बेहतर समाज बन सके। यहां रिश्ते की नींव ही लड़की के घर से मिलने वाला दहेज तय करता है।

हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत में दहेज के कारण रोज़ 21 महिलाओं की मौत होती है। शोध और अध्ययन से पता चलता है कि दहेज हत्या से संबंधित कुल घटनाएं, जो दर्ज होती हैं, उनमें से 93 फ़ीसद मामलों में चार्जशीट दाख़िल होती है और उनमें से केवल 1/3 मामले में आरोपी दोषी साबित हो पाते हैं। दहेज हत्या के संबंध में न्यूनतम दंड 7 साल की उम्रक़ैद है। दहेज हत्या के मामले में जज के पास यह अधिकार भी है कि वह अपने विवेक से आजीवन कारावास तक की सज़ा सुना सकता है। इतनी कठोरता के बाद भी दहेज के मामले कम नहीं हो रहे यह सोचनीय है।

दहेज लेना एक रूढ़ीवादी सांस्कृतिक परंपरा है जो पितृसत्ता को पोषित करती है। संस्कृति के रूप में इसे चलाए रखा जाता है और आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित किया जाता है,जिससे पितृसत्ता का वजूद बना रहे और पुरुष स्त्री को संपत्ति की तरह हासिल कर उसका स्वामी बन सके। दहेज प्रथा के कारण महिलाएं समाज में दोयम दर्जे की मानी जाती हैं। जन्म से ही उन्हें 'पराया धन' कहकर परिवार के सभी संसाधनों से अलग-थलग कर दिया जाता है। उन्हें यह संदेश दिया जाता है कि परिवार की संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तो 'दूसरे के घर' जाना है। 'दूसरे के घर' जाने का तर्क हमारे घरों में लैंगिक असमानता की नींव भी रखता है। लड़कियों को दूसरे के घर जाना होता है इसलिए उनसे पारंपरिक गुण यानी खाना पकाने से लेकर, सिलाई-बुनाई और घर चलाने के कौशल में पारंगत होने की उम्मीद की जाती है। इसीलिए, जहां भाई पढ़ता है, वहीं लड़की चौके में रोटियां बेलती है यानी पत्नी बनने की ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो जाती है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है।

वैसे दहेज की मांग और उसके बाद ससुराल में महिला शोषण की रोकथाम के लिए सरकारों से लगातार प्रयास किए गए हैं। कानून निर्माताओं ने पति और उसके परिवार वालों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए समय-समय पर नियम व कानून पारित किए हैं। इसके बावजूद भी ससुराल में महिलाओं की संदेहास्पद मौतें होती हैं। 1961 का दहेज निषेध अधिनियम, विवाह के लिए दहेज, जिसे एक उपहार के रूप में परिभाषित किया जाता है या विवाह के लिए पूर्व शर्त माना जाता है की अनुरोध, भुगतान या स्वीकृति पर प्रतिबंध लगाता है। दहेज मांगने या देने पर छह महीने की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दहेज के संबंध में हत्या और आत्महत्या के मामले क्रिमिनल पीनल कोड और इंडियन पीनल कोड के तहत देखे जाते हैं।अब देखते है ट्विशा शर्मा को कानूनी रूप से क्या इंसाफ मिलता है ।

महत्त्वपूर्ण
Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law. **Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

गर्मी

गाजियाबाद के वेव सिटी में भीषण गर्मी के बीच एक मां अपने बच्चों के साथ वाहन पर सफर करती नजर आई।

ब्रिटेन में 23 वर्षीय युवक बना भारतीय मूल का सबसे युवा मेयर

लंदन/भाषा। पूर्वी इंग्लैंड की एक स्थानीय परिषद का प्रतिनिधित्व करने वाले 23 वर्षीय युवक ने ब्रिटेन में सबसे कम उम्र का भारतीय मूल का मेयर बनकर इतिहास रच दिया है। किंग्स कॉलेज लंदन के राजनीति विज्ञान के पूर्व छात्र तुषार कुमार ने पिछले सप्ताह एक समारोह में एल्स्ट्री और बोरेहमवुड के मेयर का पदभार ग्रहण किया। लेबर पार्टी के पार्षद कुमार 2023 में एल्स्ट्री और बोरेहमवुड नगर परिषद में शामिल हुए थे और पूर्व में उन्होंने उप महापौर के तौर पर सेवा दी है। समारोह के बाद जारी एक बयान में कुमार ने कहा, ''कल रात एल्स्ट्री और बोरेहमवुड के महापौर के रूप में आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करना मेरे लिए सम्मान की बात है और 23 वर्ष की आयु में, मैं ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम उम्र का भारतीय मूल का महापौर बना हूं।'' कुमार का मानना है कि ''वास्तविक परिवर्तन सामुदायिक स्तर पर शुरू होता है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे स्वयंसेवा करना, समावेशी सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करना और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच की पैरोकारी करना पसंद है।''

भारत-नीदरलैंड साझेदारी: डच कालीन ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली/पटना/भाषा। भारत और नीदरलैंड के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाए जाने के बीच दोनों देशों के इतिहासकारों और वास्तु विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि इससे भारत में डच कालीन स्थापत्य संबंधी विरासत के बेहतर संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा।

इतिहासकारों को उम्मीद है कि अब डच कालीन विरासतों का बिहार की राजधानी पटना स्थित कलेक्ट्रेट भवन की तरह पतन नहीं होगा जिसे चार साल पहले ध्वस्त कर दिया गया था।

विशेषज्ञों ने पटना कलेक्ट्रेट भवन का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की दिशा में अब गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।

मई 2022 में बुलडोजरों द्वारा ऐतिहासिक पटना कलेक्ट्रेट परिसर को गिराए जाने की तस्वीरें आज भी उन लोगों के मन में ताजा हैं, जिन्होंने सदियों पुराने इस परिसर को बचाने के लिए अभियान चलाया था। इस परिसर में कई विरासत संरचनाएं थीं, जिनमें प्रतिष्ठित रिकॉर्ड रूम भवन भी शामिल था, जिसका निर्माण डच काल में और बाद में ब्रिटिश राज में कराया गया था। भव्य स्तंभों वाले रिकॉर्ड रूम भवन को हाल तक पटना के बीचों-बीच डच वास्तुकला के दुर्लभ नमूने के रूप में देखा जाता था, लेकिन 17 मई 2022 को लोगों के विरोध के बावजूद इसे ध्वस्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 से 17 मई तक नीदरलैंड की यात्रा की, जिसके दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक विस्तारित किया। इस घटनाक्रम के बीच पटना से लेकर बर्लिन तक बिहार के लोगों ने डच कालीन विरासत स्थल के महत्व को याद करते हुए उसके नष्ट होने पर अफसोस जताया।

बर्लिन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे दिप्तांशु सिन्हा ने कहा, पटना कलेक्ट्रेट को ध्वस्त किया जाना केवल गलत निर्णय नहीं था, बल्कि साझा विरासत की बड़ी क्षति थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी से बिहार तथा देश के अन्य हिस्सों में बची डच कालीन विरासत इमारतों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सिन्हा ने कहा कि भारत और यूरोप के बीच सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा होती रही है, लेकिन दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए इन संबंधों की सबसे ठोस अभिव्यक्ति उस दौर की विरासत इमारतों के रूप में दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो दशकों में बिहार सरकार ने पटना की कई ब्रिटिश कालीन सार्वजनिक इमारतों को हटाया और वर्ष 2022 में डच कालीन पटना कलेक्ट्रेट को भी ध्वस्त कर दिया, जबकि इसे संरक्षित कर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता था।

पटना के विरासत विशेषज्ञों ने भी माना कि पुराने कलेक्ट्रेट परिसर के ध्वस्तीकरण के साथ शहर का एक बड़ा 'डच संबंध' समाप्त हो गया। सिन्हा 'सेव हिस्टोरिक पटना कलेक्ट्रेट' अभियान से जुड़े रहे, जिसने छह वर्षों तक इस ऐतिहासिक परिसर को बचाने के लिए संघर्ष किया था।

कलेक्ट्रेट भवन को ध्वस्त करने से नष्ट हुई अन्य प्रमुख इमारतों में ब्रिटिश कालीन जिलाधिकारी कार्यालय भवन, डच कालीन जिला अभियंता कार्यालय भवन, एसडीओ कार्यालय भवन और भूमि अधिग्रहण कार्यालय भवन शामिल थे। वर्ष 2020 में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रिकॉर्ड रूम भवन के अग्रभाग के आठ स्तंभों को बचा लिया गया था। इन्हें दिसंबर 2024 में उद्घाटित नए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शित किया गया। पटना कलेक्ट्रेट संरक्षण के समर्थक डच इतिहासकार लेनार्ट बेस ने कहा कि भारत और नीदरलैंड के बीच नई रणनीतिक साझेदारी से भारत में डच विरासत के प्रति अधिक जागरूकता पैदा होगी और भविष्य में ऐसी धरोहरों को नष्ट होने से बचाया जा सकेगा।

आईपीएल में केएल राहुल की रिकॉर्ड तोड़ पारी से खुश हुए सुनील शेट्टी

मुंबई/एजेन्सी

'आईपीएल- 2026' में केएल राहुल लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतक लगाकर एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। राहुल ने आईपीएल में आठवीं बार एक सीजन में 500 से ज्यादा रन पूरे किए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। फैंस के साथ-साथ परिवार भी राहुल की इस उपलब्धि पर काफी खुश है। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी अपने दामाद की इस कामयाबी पर खास अंदाज में खुशी जाहिर की। सुनील शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर केएल राहुल का एक पोस्टर साझा किया। इस पोस्टर में राहुल की तस्वीर के साथ उनकी उपलब्धि की जानकारी दी गई थी कि उन्होंने आईपीएल में आठवीं बार 500 से ज्यादा रन पूरे कर लिए हैं। पोस्टर में राहुल बैटिंग फॉर्म में नजर आ रहे है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए सुनील शेट्टी ने ऊपर की तरफ 'नजर' से बचाने वाली इमोजी भी लगाई। सुनील शेट्टी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फैंस को भी अभिनेता का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है।

बता दें कि सोशल मीडिया पर राहुल और सुनील शेट्टी के बीच हमेशा अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती रही है और कई मौकों पर वह खुले तौर पर राहुल की तारीफ करते भी नजर आ चुके हैं।

अगर राहुल के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में 42 गेंदों में 56 रनों की दमदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने एक चौका और तीन छक्के लगाए। राहुल की बल्लेबाजी के चलते दिल्ली कैपिटल्स ने मैच में मजबूत पकड़ बनाई और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

कान्स फिल्म फेस्टिवल में छाई 'बॉम्बे स्टोरीज'

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री अनुप्रिया गोयनका इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'बॉम्बे स्टोरीज' को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। यह फिल्म कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही है। किसी भी कलाकार के लिए कान्स तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है और अनुप्रिया के लिए भी यह मौका बेहद खास है, क्योंकि यह उनकी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म है। फिल्म का निर्देशन राहत शाह काजमी ने किया है और इसकी कहानी मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो की चर्चित कहानी 'हतक' से प्रेरित है।

फिल्म में समाज के उस हिस्से की कहानी दिखाई गई है, जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते। फिल्म 'बॉम्बे स्टोरीज' में अनुप्रिया गोयनका एक सेक्स वर्कर के किरदार में हैं। उनके साथ फिल्म में मौनी रॉय और सुष्मिता सिंह भी अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। फिल्म में सेक्स वर्कर्स की जिंदगी, उनके संघर्ष, समाज के नजरिए और उनके भीतर छिपी भावनाओं को दिखाने की कोशिश की गई है। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अनुप्रिया ने कहा, मैं लंबे समय से इंडिपेंडेंट सिनेमा का हिस्सा बनना चाहती थीं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरी पहली फिल्म मंटो की कहानी पर आधारित है। 'हतक' शब्द का मतलब अपमान होता है और फिल्म की कहानी भी इसी भावना के इर्द-गिर्द घूमती है। मेरा किरदार सौगंधी समाज की नजरों और लोगों के फैसलों के बीच खुद को समझने की कोशिश करती है।

अभिनेत्री ने अपने किरदार को समझाते हुए कहा, सौगंधी एक ऐसी महिला है, जिसने अपनी जिंदगी को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके दिल में भी प्यार और सम्मान पाने की चाहत है।

वह चाहती है कि कोई उसे सिर्फ शरीर की नजर से न देखे, बल्कि उसे एक इंसान और एक महिला के रूप में महसूस करे। इस किरदार में मुझे खुद की कई भावनाएं नजर आईं। मैंने इस किरदार को निभाते हुए एक महिला के कई अलग-अलग पहलुओं को समझा और महसूस किया।

अनुप्रिया गोयनका ने सेक्स वर्क को लेकर कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से यह काम चुनता है, तो यह उसका अधिकार और उसका फैसला है। इसे किसी दूसरे पेशे की तरह ही देखा जाना चाहिए। लेकिन जब किसी महिला को मजबूरी में इस काम में धकेला जाता है, उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं या उसे इंसान की तरह सम्मान नहीं मिलता, तब यह गलत और दुखद बन जाता है।

उन्होंने कहा, समाज में सेक्स वर्कर्स को अक्सर सिर्फ एक वस्तु की तरह देखा जाता है, जबकि उनके भी सपने, भावनाएं हैं और उन्हें भी सम्मान की जरूरत होती है। जब तक किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ इस काम में मजबूर नहीं किया जाता, तब तक समाज को उसे जज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

दलाई लामा से मुलाकात कर भावुक हुईं भूमि पेडनेकर, बोलीं- 'लौटते वक्त आंखों से बहने लगे आंसू'

धर्मशाला/एजेन्सी

भूमि पेडनेकर इन दिनों सिर्फ अपनी फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों को लेकर भी चर्चा में हैं। इस बीच, वह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचीं, जहां उन्होंने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात की। यह मुलाकात भूमि के लिए बेहद खास रही। उन्होंने इस अनुभव को अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ साझा किया। भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह दलाई लामा के साथ बैठी नजर आईं, जबकि कुछ तस्वीरों में धर्मशाला की खूबसूरत वादियां और वहां के आध्यात्मिक वातावरण की झलक दिखाई दी। पोस्ट के कैप्शन में भूमि ने लिखा, दलाई लामा की मौजूदगी में मुझे सब कुछ बहुत हल्का, शांत और किसी सपने जैसा महसूस हुआ। जैसे ही मैं वहां से वापस लौटी, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इस एहसास को शब्दों में पूरी तरह बताना आसान नहीं है। यह अनुभव मैंने दिल से महसूस किया।

भूमि ने आगे कहा, मैं पिछले कुछ समय से खुद को समझने और मानसिक शांति पाने की यात्रा पर हूं। जिंदगी में मिलने वाले ऐसे खास पल मुझे भगवान और जीवन के प्रति ज्यादा शुक्रगुजार बना देते हैं। दलाई लामा से मिलना मेरे लिए शांति, दया और प्रेम से भरा ऐसा अनुभव था, जिसे मैं जिंदगीभर याद रखूंगी।

भूमि की इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। दलाई लामा का जीवन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा है। साल 1959 में तिब्बत में चीन के शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था। हालात बिगड़ने के बाद दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा। वह अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय पार करके भारत पहुंचे थे।

उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश में शरण दी थी। बाद में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती निर्वासित सरकार का केंद्र बनाया गया, जो आज भी तिब्बती समुदाय के लिए बेहद अहम जगह मानी जाती है। दलाई लामा को भारत में शरण दिए जाने के बाद भारत और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। उसी दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी गहराने लगे। धीरे-धीरे यह तनाव इतना बढ़ा कि साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया। इस युद्ध ने दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा असर डाला।

'अम्मा अरियान' कान फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई

नयी दिल्ली/भाषा

मलयालम की बहुचर्चित फिल्म ''अम्मा अरियान'' को कान फिल्म महोत्सव की क्लासिक श्रेणी में नए सिरे से पुनर्स्थापित 4के संस्करण में प्रदर्शित किया गया। मूल रूप से 1986 में रिलीज हुई, 115 मिनट लंबी यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे क्रांतिकारी कृतियों में से एक मानी जाती है।

इसका निर्देशन दिवंगत जॉन अब्राहम ने किया था, जो अपनी राजनीतिक रूप से प्रेरित और अपरंपरागत कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते थे। ''अम्मा अरियान'' 1987 में जॉन के निधन से पहले उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म का प्रदर्शन शनिवार को दक्षिणी फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा स्थित कान शहर में आयोजित समारोह में हुआ और यह क्लासिक श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म थी।

इवेंट

मुंबई में आगामी फिल्म 'सिस्टम' के प्रमोशनल इवेंट के दौरान अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका सरवनन ने कैमरों के सामने पोज दिए।

बॉक्स ऑफिस पर 'करुप्पु' का दबदबा, आयुष्मान खुराना और संजय दत्त की फिल्में फीकी पड़ीं

मुंबई/एजेन्सी

इस शुक्रवार सिनेमाघरों में तीन बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। सूर्या की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'करुप्पु', आयुष्मान खुराना की रोमांटिक-कॉमेडी 'पति पत्नी और वो 2' और संजय दत्त अभिनीत आखिरी सवाल एक साथ रिलीज हुईं। पहले दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों ने साफ कर दिया कि दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार सूर्या की फिल्म को मिला है। सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'करुप्पु' ने रिलीज के पहले दिन देशभर में 14.40 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की। आर्थिक दिक्कतों और शुरुआती शोज रद्द होने जैसी चुनौतियों के बावजूद फिल्म ने दमदार शुरुआत की है। आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सूर्या एक ऐसे वकील और योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, जो अदालत और संघर्ष दोनों में अपनी ताकत दिखाता है। फिल्म में तृषा कृष्णन, योगी बाबू, स्वासिका और इंद्रन्स भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।

वहीं 'पति पत्नी और वो 2' दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल नहीं रही। फिल्म ने पहले दिन केवल 3.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जो इसके प्रीक्वल पति पत्नी और वो की ओपनिंग से काफी कम है।

दूसरी ओर 'आखिरी सवाल' का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन महज 40 लाख रुपये की कमाई की। फिल्म में अमित साध और नमाशी चक्रवर्ती भी अहम भूमिकाओं में हैं, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रिया ठंडी रहने से इसका असर कमाई पर साफ दिखाई दिया।

उल्का गुप्ता की 'रजनी की बारात' का टीजर रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

रोमांस, कॉमेडी और मेलोड्रामा से भरपूर फिल्म 'रजनी की बारात' का बहुप्रतीक्षित टीजर रिलीज हो गया है। दरभंगा की खूबसूरत लोकेशंस और देसी बिहारी अंदाज में बनी इस फिल्म में अभिनेत्री उल्का गुप्ता एक दमदार किरदार निभाती नजर आ रही हैं। करीब एक मिनट के टीजर की शुरुआत बिहारी स्टाइल 'लौंडा नाच' के अनाउंसमेंट से होती है, जिसके बाद उल्का का दमदार डायलॉग सुनाई देता है, हमको रञ्जन से शादी करनी है। टीजर में कॉमिक, रोमांटिक और इमोशनल पलों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है।

टीजर में इशिता सिंह का संवाद रञ्जन जी से मिलकर स्पेशल तो लगा कहानी में लव ट्रायंगल का ट्विस्ट जोड़ता है। वहीं सुनीता राजवार अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाती नजर आती हैं। जरीना वहाब और सुनीता राजवार के डांस सीक्वेंस भी टीजर का खास आकर्षण बने हैं। अंत में पुलिस ऑफिसर के रोल में अश्वथ भट्ट की एंट्री और उनका संवाद लव स्टोरी बहुत प्यारा है सर' कहानी में नए रोमांच का संकेत देता है। टीजर में उल्का गुप्ता, कनिष्क, सुनीता राजवार और अश्वथ भट्ट के किरदारों की दमदार झलक देखने को मिली है।

एपिफेनी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी 'रजनी की बारात' का निर्माण तनाया आडारकर प्रभु और तेज एच आडारकर ने किया है, जबकि निर्देशन आदित्य अमन ने संभाला है। फिल्म में उल्का गुप्ता, कनिष्क, इशिता सिंह, जरीना वहाब, सुनीता राजवार और अश्वथ भट्ट मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। टीजर लॉन्च के दौरान उल्का गुप्ता ने कहा कि रजनी का किरदार एक ऐसी लड़की का है, जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि फिल्म में इमोशन, कॉमेडी और ड्रामा का बेहद दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलेगा। 'रजनी की बारात' 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

अभय श्रीश्रीमाल की पुस्तक 'सबक' का लोकार्पण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन एजुकेशनल सोसायटी के महासचिव अभयकुमार श्रीश्रीमाल जैन द्वारा अपने व्यावसायिक अनुभवों के आधार पर लिखित पुस्तक 'सबक' (सटीक बदलाव की कहानियाँ) का लोकार्पण रविवार को शाम रिपन बिल्डिंग परिसर में स्थित विक्टोरिया सभागार में हुआ। यह उनकी अंग्रेजी पुस्तक 'ब्लास्ट' का हिंदी अनुवाद साहित्यकार डॉ. दिलीप धींग द्वारा किया गया है। संयोजक गोविंद मूंदड़ा ने लेखक और अनुवादक का परिचय दिया। विमोचन के बाद लेखक श्रीश्रीमाल ने पहली प्रति शसुन जैन महाविद्यालय में जैनविद्या विभाग के निदेशक डॉ. ज्ञान जैन को दी। श्रीश्रीमाल ने हिंदीभाषियों के लिए पुस्तक उपलब्ध करवाने के लिए अनुवादक डॉ. दिलीप धींग को धन्यवाद दिया और पाठकों से अनुरोध किया कि वे पुस्तक के बारे में सुझाव दें।

पुस्तक का विस्तृत परिचय देते हुए अनुवादक डॉ. धींग ने कहा, वैश्विक उद्योग जगत की शब्दावली को हिंदी में लाना एक रोचक अनुभव रहा। अनुवाद साहित्य की एक विधा है, कला है। श्रेष्ठ अनुवाद में अनुसृजन और संपादन का स्पर्श भी होता है।

भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के पूर्व सचिव टी. रामसामी के संदर्भ से डॉ. धींग ने कहा कि भारत के विकास में नेतृत्व, उद्यमशीलता और सांस्थानिक आधारभूत संरचना आवश्यक है और सबक' एकमात्र पुस्तक है, जो इन तीनों विषयों को एक साथ समझाती है।

डॉ. धींग ने बताया कि श्रीश्रीमाल ने अपने विशेष लेबल के जरिए किसी समय दक्षिणी राज्यों में मदिरा के अवैध व्यापार और निर्बाध परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद की। उन्होंने बताया कि लेखक द्वारा चिकित्सा में प्रयुक्त स्टेम सेल तकनीक से तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. कलाम भी प्रभावित हुए थे। डॉ. धींग ने कहा कि यह पुस्तक व्यवसाय करने वालों के साथ ही उनके लिए भी उपयोगी है, जो उद्देश्य के साथ नेतृत्व करना, जीवन को गढ़ना और आगे बढ़ना चाहते हैं।

सबक' के विमोचन के बाद शकुंतला करनानी की पुस्तक 'शकुंतलम' का विमोचन और प्रदीप सक्सेना की गजल संध्या अर्ज किया है' हुई। इस अवसर पर उषा श्रीश्रीमाल, सुभाषचंद रांका, मयूर-दीपक श्रीश्रीमाल, अशोक मेहता, शांतिलाल जैन, मोहिनी चोरड़िया, पारस संचेती, मदनलाल गुंदेचा, गौतम बोहरा, ग्वालदास करनानी सहित महानगर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

कमलसिंह दुगड़ फिर बने तेरापंथी सभा राजराजेश्वरीनगर के अध्यक्ष

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। तेरापंथी सभा, राजराजेश्वरीनगर की रविवार को आयोजित वार्षिक साधारण सभा तेरापंथ भवन में आयोजित हुई। पूर्व अध्यक्ष मनोज डागा ने श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन किया। अध्यक्ष राकेश छाजेड़ ने सभी का स्वागत करते हुए आचार्यश्री व साध्वियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने अपने 2 वर्षीय कार्यकाल की सफलता का श्रेय गुरु, पूर्व अध्यक्ष व टीम, तेयुप व महिला मंडल सहित सभी सहयोगियों को दिया। मंत्री गुलाब बाँठिया ने कार्यकाल की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी।कोषाध्यक्ष देवेन्द्र नाहटा ने आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया।

ज्ञानशाला संयोजिका नीतू बाफना ने ज्ञानशाला, संगठन मंत्री अमित नौलखा ने नए सदस्य अभियान व सदस्यों की जानकारी दी। उपाध्यक्ष सरोज बैद ने राकेश छाजेड़ के अभिनंदन पत्र का वाचन किया। बैठक में अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। गणपतलाल कोठारी को आगामी दो वर्ष हेतु पुनः अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। चुनाव अधिकारी मनोज डागा एवं सहअधिकारी सुशील भंसाली (छापर) ने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चुनाव में एक भी नामांकन पत्र प्राप्त न होने का कारण वर्ष 2026-28 के लिए मनोननय से अध्यक्ष पद हेतु कमलसिंह दुगड़ के नाम की घोषणा की। सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति दी और दुगड़ का चयन हुआ। राकेश छाजेड़ व उनकी टीम ने नवमनोनीत अध्यक्ष का स्वागत किया। ट्रस्ट, तेयुप, तेममं, समण संस्कृति संकाय, ज्ञानशाला परिवार सहित उपस्थित गणमान्य सदस्यों ने नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाइयां दी।

कमल दुगड़ ने सभी को साथ लेकर चलने की अपनी भावना व्यक्त की। सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। गुलाब बाँठिया ने संचालन किया। निवर्तमान व नए अध्यक्ष ने मंगलपाठ श्रवण हेतु साध्वीश्री पावनप्रभाजी के दर्शन किए।

अन्नदान — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

रॉयल्स परिवार संस्था के 30वें वर्ष के उपलक्ष में रविवार को केके नगर स्थित अक्षय ट्रस्ट वृद्धाश्रम में अन्नदान का कार्यक्रम रखा गया। सदस्यों ने वृद्ध बुजुर्गों का दोपहर का भोजन करवाया। अध्यक्ष जितेंद्र मुणोत की उपस्थिति में अन्नदान टीम के गणपत कोठारी, महावीर छाजेड़ और ज्ञानेंद्र बाघमार ने सेवा कार्य में सहयोग दिया।

मदर्स डे — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

भारतीय जैन संगठन (बीजेएस) मदुरै शाखा ने मदर्स डे के उपलक्ष्य में अनाथालय के बच्चों व महिलाओं को भोजन कराया तथा वस्त्र प्रदान किए। इस सेवा कार्य में अध्यक्ष जीतेन्द्र गोलेछा, सचिव जीतेन्द्र छाजेड़, वैगाई रीजन के अध्यक्ष जयकिरण जैन, महिला अध्यक्ष रेणुका गोलेछा और महिला सचिव दीपिका भंडारी सहित अन्य सदस्यों ने सहयोग दिया। इस मौके पर बच्चों व महिलाओं को उपहार भी दिए गए।

'वित्तीय व्यवसाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका' विषय पर कार्यशाला का आयोजन

मद्रास हायर परचेज़ एसोसिएशन ने किया आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय मद्रास हायर परचेज़ एसोसिएशन द्वारा एगमोर स्थित राजस्थानी एसोसिएशन के नए हॉल में 'वित्तीय व्यवसाय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रजत के पंजीकृत सदस्यों की सौ फीसदी उपस्थिति थी।। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थानी एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत चोरड़िया तथा विशिष्ट अतिथि एफआईएएफए के अध्यक्ष दिनेश कोठारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विद्वान सौरव जैन ने वित्तीय व्यवसाय के क्षेत्र में एआई के व्यावहारिक उपयोग पर बहुमूल्य जानकारी साझा की, जिसमें ग्राहक सत्यापन, दस्तावेज़ प्रसंस्करण, सीआरएम, रिपोर्ट निर्माण, वसूली प्रबंधन और व्यवसाय संवर्धन शामिल हैं। उन्होंने रजत सदस्यों को संबोधित करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि एआई किस प्रकार व्यवसायों को गति, दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने में महत्वपूर्ण मदद कर रहा है और हम सभी का जीवन सरल बना रहा है। मद्रास हायर परचेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर कहा कि वे अपने सदस्यों के पेशेवर और व्यावसायिक विकास में सहयोग करने के लिए इस प्रकार की और भी कई शिक्षण-उन्मुख कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए उत्सुक है ।

समाजहित में शुरू की अनेक योजनाएं, विशेषांक का किया लोकार्पण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के एक होटल में रविवार को लोकार्पण व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील शर्मा द्वारा इस समाज के कल्याण के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी हेतु सामाजिक विशेषांक के रूप में मगबन्धु पत्रिका का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सुनील शर्मा, जयपुर के कुलदीप व्यास, किशोर शर्मा, डॉ सुधांशु शेखर मिश्र, संतोष शर्मा, चंद्रा शर्मा आदि द्वारा भगवान भास्कर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में मगबन्धु पत्रिका के संपादक डॉ सुधांशु शेखर मिश्र ने समारोह में लोकार्पित होने वाले विशेषांक की विषय वस्तु व मग-ब्राह्मण के इतिहास की जानकारी दी। सुनील शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने मगबन्धु पत्रिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद साहित्यकार डॉ. मदन मोहन 'तरुण' एवं डॉ. मणिकांत मिश्र ने विशेषांक पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत की।

दूसरे सत्र में 'सुनील शर्मा शिक्षा फाउंडेशन' द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रोग्राम के तहत शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बीआईजीआई में शाकद्वीपीय समाज के नौ विद्यार्थियों के एक वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के लिए सहयोग दिया गया तथा उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम की कड़ी में 'समाज के द्वारा, समाज के लिए' अभियान के तहत 'सुनील शर्मा जनआरोग्य कनेक्ट' नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य इसके माध्यम से पूरे देश भर के शाकद्वीपीय समुदाय के डॉक्टरों का एक पैनल बनाकर समाज के सदस्यों को मेडिकल सुविधा व परामर्श उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में शकद्वीपीय समाज सहित अन्य समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन चेतन शर्मा ने किया।

मैलापुर में आयोजित नेत्र व दंत जांच चिकित्सा शिविर में 148 लोग हुए लाभान्वित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन मेडिकल रिलीफ़ सोसाइटी की ईकाई मैलापुर स्थित खींवराज चोरड़िया मेमोरियल डायलेसिस सेंटर व जेवंतमल चोरड़िया डायग्नोस्टिक सेंटर में रविवार को नेत्र जांच व दंत जांच चिकित्सा शिविर सम्पन्न हुआ। हरीश, सौरव, गौरव कांकरिया परिवार के सौजन्य से आयोजित शिविर में भगवान महावीर आई हास्पिटल रायपुरम की टीम द्वारा 148 लोगों की नेत्र जांच की गई, जिसमें 19 व्यक्तियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। 97 जरूरतमंदों को चश्मे बना कर दिए जाएंगे तथा 148 जनों के दांतों की जांच की गई। शिविर को सफल बनाने में चेयरमैन कांतादेवी चोरड़िया, मंत्री निर्मला लोढ़ा, कोषाध्यक्ष किशोर झामड़, सोसाइटी अध्यक्ष अशोक कुमार मेहता, महामंत्री राजकुमार दुगड़, कैलाशमल दुगड़, अजय दुगड़, कमल खाबिया, महावीर बोहरा, प्रवीण छाजेड़, रतन बैद आदि का सहयोग मिला।

'रेदासनी बॉक्स क्रिकेट कप' के लिए खिलाड़ियों की हुई नीलामी

ब्यावर संघ युवा शाखा द्वारा 7 जून को होगा आयोजन

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। स्थानीय ब्यावर संघ के तत्वावधान में ब्यावर संघ युवा शाखा द्वारा आयोजित 'रेदासनी बॉक्स क्रिकेट कप' बीएसपीएल सीजन-4 के लिए 12 पुरुष की और 4 महिला टीम के लिए एक सौ साठ खिलाड़ियों का ऑक्शन सम्पन्न हुआ। ब्यावर संघ के अध्यक्ष ललित डाकलिया, कोषाध्यक्ष दिनेश लोढा, सहमंत्री विनय राठौड़, संगठनमंत्री किशन सोलीवाल के साथ युवा शाखा के अध्यक्ष कुलदीप छाजेड़, उपाध्यक्ष विकास खटोड़, नरेश बोहरा, महामंत्री चेतन रेदासनी, कोषाध्यक्ष हेमंत गुलेच्छा, सहमंत्री भरत कोठारी, सहकोषाध्यक्ष कुणाल मरलेचा ने दीप प्रज्वलन किया। महिला विंग की चंद्रकला डाकलिया, कंचन छाजेड़ एवं सीमा बोहरा ने मंगलाचरण किया। बीएसपीएल प्रतियोगिता का आयोजन 7 जून को होगा। बीएसपीएल के कार्यों का संचालन करने में खेल समिति के यशवन्त रांका, रोशन लोढ़ा के साथ भोजन समिति के अल्केश हिंगड, मनीष बाफना एवं तकनीकी टीम के महावीर गुगलिया एवं अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता के मुख्य प्रायोजक चेतनकुमार रश्मीदेवी रेदासनी हैं जिन्होंने युवा शाखा कार्यकारिणी के साथ ट्राफी का अनावरण किया। भोजन प्रायोजक पुखराज चंचलदेवी श्रीश्रीमाल परिवार के साथ टी-शर्ट प्रायोजक सज्ञनराज कोठारी ने सभी टीमों के लिए टी शर्ट कलर विकल्प का ड्रा निकाला। ऑक्शन प्रायोजक राजेन्द्रकुमार अरिहंतकुमार रेदासनी परिवार, खेल ग्राउंड प्रायोजक अनिल कोठारी परिवार, कैप प्रायोजक गुमानचन्द बोहरा परिवार, टॉस का बॉस विजय सिंघवी परिवार, किट प्रायोजक दिनेश तातेड़ परिवार, शीतल पेय प्रायोजक नोरतमल नाहर परिवार, बूम बूम ओवर प्रायोजक नरेश बोहरा का अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ। टूर्नामेंट हेतु पुरुष वर्ग की बारह टीम मयूर कंप्यूटर मार्वल्स, तनिष्का तूफान, कुमट वॉरियर्स, मणिधारी पैंथर्स, मां क्रिएशंस, कक्कड़ वॉरियर्स, गोलेच्छा ग्लेडिएटर्स, हितेन मेवेरिक्स, कोठारी एलजीसी चैलेंजर्स, एजिंग 100 प्रतिशत क्रिकेटर्स, संचेती वॉरियर्स, पंजाबी तड़का वॉरियर्स के साथ महिलाओं की सूरज स्ट्राइकर्स, क्वींस स्ट्राइकर्स, दिनेश एसोसिएट्स, बम्ब ब्लास्टर आदि टीमों ने अपने मनचाहे खिलाड़ी खरीदे।

कोयम्बटूर में आयोजित हुई तेरापंथ महिला मंडल की संगठन यात्रा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयम्बटूर। शहर के गांधी पार्क स्थित तेरापंथ भवन में सोमवार को संगठन यात्रा हेतु अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की तमिलनाडु केरल प्रांत की प्रभारी अनीता बरड़िया एवं शालिनी लुंकड़ पहुंची। साध्वीश्री सिद्धप्रभाजी के सान्निध्य में नवकार मंत्र के उच्चारण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अध्यक्ष रुपकला भंडारी ने सभी का स्वागत किया। शालिनी लुकंड ने अभातेममं की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारियां प्रदान की। अनीता बरड़िया द्वारा जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। साध्वीश्री सिद्धप्रभाजी ने महिला मंडल को प्रेरणा पाथेय प्रदान किया। कोयम्बत्तूर महिला मंडल द्वारा भावना चौका हेतु अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल को अनुदान दिया गया । कार्यक्रम का संचालन सहमंत्री वंदना पारख ने किया। मंत्री रेखा मरोठी ने धन्यवाद दिया।

आचार्यश्री नित्यानंदसूरी के चातुर्मास की तैयारियों के लिए बैठकों का दौर शुरू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के लालबाग रोड स्थित गोड़वाड़ भवन में पद्मश्री से सम्मानित गच्छाधिपति आचार्यश्री नित्यानंदसूरीश्वरजी का इस वर्ष का चातुर्मास तय है और 19 जुलाई को उनका चातुर्मासार्थ मंगल प्रवेश होगा। चातुर्मास की तैयारियों को लेकर अशोककुमार बम्बोली की अध्यक्षता में गोड़वाड़ भवन में रविवार को एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें गोड़वाड़ महासभा के महामंत्री प्रवीण कुमार चांदावत ने सभी का स्वागत किया। गोडवाड़ भवन ट्रस्ट के वरिष्ठ कुमारपाल सिसोदिया ने आचार्यश्री के नगर प्रवेश, संक्रांति महोत्सव व चातुर्मास प्रवेश के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गोडवाड़ भवन ट्रस्ट के महामंत्री विक्रम कुमार करबावाला ने बताया कि चातुर्मास के दौरान आराधकों के लिए 50 दिवसीय आराधना, साधना व तपस्या हेतु फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसमें 150 से 175 आराधकों के ठहरने व्यवस्था की जा रही है। भवन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भंवरलाल करबावाला ने कहा कि भवन में संतों व श्रद्धालुओं की सुविधा व आराधना के लिए भवन में ही चल प्रतिष्ठित प्रतिमाएं विराजित कर अस्थाई मंदिर भी बनाया जा रहा है। बैठक में किरण कांकरिया एवं महीपाल सुराणा ने भी अपने विचार रखे व गुरु वल्लभ के उपकारों का स्मरण किया।

आचार्यश्री नित्यानंदसूरीश्वरजी

बैठक में भवन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष राजेश कुमार राठौड़, रमेशकुमार चांदावत, अशोक करबावाला, रंगराज हिंगड़, महासभा के वसंत सोलंकी, भरत सेमलानी, निर्मल कुमार धोका, गोपाल सिसोदिया, नवरतनमल पारेख, प्रकाश सोलंकी, प्रतीक मेहता, दर्शन राणावत, दलपत जैन, निहालचंद मेहता, नगराज सेठिया, नरेंद्र गिरिया आदि उपस्थित थे।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.